सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 34, नई दिल्ली । सोमवार, 14 अप्रैल 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

03 अपनी जन्मस्थली पर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करना मेरा सौभाग्य --

06 स्मार्ट खेती खोलती किसान के बेहतर भविष्य की राह

08 मेयर सुलोचना दास ने अपराजिता शारंगी को आरोप : पार्टी उसके लिए बड़ी है लेकिन

उपायुक्त आटो टैक्सी द्वारा जारी किया गया अनोखा आदेश

संजय बाटला

नई दिल्ली । दिल्ली परिवहन विभाग के आटो टैक्सी उपायुक्त द्वारा सुर्खियों में आने या किसी विशेष समूह को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ऐसा आदेश जारी कर दिखाया जिसके बारे मे वर्षों पहले से ही मोटर वाहन अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों में धारा 82 में उपलब्ध था। इस आदेश के अनुसार क्या कहा गया स्वयं पढ़े नीचे हिन्दी रूपांतर में

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

परिवहन विभाग ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनिट 5/9 अंडर हिल रोड दिल्ली-110054

एफ. नं. डीटीओ/(एआरयू एवं टीयू)/टीपीटी/2023/980/सीडी-075744304/16599 दिनांकः 09/04/2025

आदेश

राज्य परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन के अनुसरण में, सं.एफ.एएस/एसटीए/टीपीटी/2021/एसटीए (बी)/15528 दिनांक 03.04.2025 को संकल्प संख्या 06

(ए)/2025 के रूप में, आदेश संख्या डीसी/(एआरयू)/टीपीटी/2011-12/1149-56 दिनांक 8 अगस्त, 2012 के तहत जारी परमिट शर्त निम्नानुसार संशोधित की जाती है-

खण्ड 4-

ऑटो रिक्शा परमिट ऑटो रिक्शा के प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से एक (01) वर्ष तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा, सिवाय परमिट धारक की मृत्यु के मामले में, जैसा कि एमवी अधिनियम, 1988 की धारा 82 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित है। उसके बाद, उसी श्रेणी से संबंधित किसी व्यक्ति को हस्तांतरण पर विचार किया जा सकता है। यदि मृतक परमिट धारक का कानूनी उत्तराधिकारी नाबालिग है या उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसवी बैज नहीं है, तो वह परिवहन विभाग, दिल्ली द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस और बैज वाले ड्राइवर को काम पर रख सकता है।

ऑटो-रिक्शा के लिए परमिट हस्तांतरण हेतु उपरोक्त परमिट शर्तें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

उप आयुक्त ऑटोरिक्शा और टैक्सी यूनिट

एफ. नं. डीटीओ/(एआरयू एवं टीयू)/टीपीटी/2023/980/सीडी-075744304/16599 दिनांकः 09/04/2025

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपिः

1. सचिव, माननीय परिवहन मंत्री (दिल्ली), दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002।

2. अपर मुख्य सचिव सह आयुक्त (परिवहन) के निजी सचिव, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002।

3. सचिव, एसटीए/विशेष आयुक्त (एआरयू एवं टीयू) के निजी सहायक, 5/9 अंडरहिल रोड, दिल्ली।

4. सभी उपायुक्त, परिवहन विभाग, 5/9 अंडरहिल रोड, दिल्ली।

5. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि आदेश को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए तथा उपर्युक्त संशोधन के अनुसार वाहन पोर्टल में सॉफ्टवेयर में संशोधन के लिए एनआईसी के साथ मामला उठाया जाए।

अति विशेष सूचना

"परिवहन विशेष" हिन्दी दैनिक समाचार पत्र आर.एन.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त करने के बाद से आपके द्वारा प्राप्त भरपूर सहयोग से मार्च में अपने 2 साल पूरे कर रहा है। इन दो सालों में समाचार पत्र को निष्पक्ष रूप से चलाने में आप सभी का भरपूर सहयोग रहा हैं जिसके लिए प्रशासनिक विभाग परिवहन विशेष आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता है और आशा करता है की भविष्य में भी आपका सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। इन दो सालों में समाचार पत्र को राष्ट्रीय स्तर पर सभी शहरों और जिलों तक पहुंचाने और वहां की सही और सच्ची खबरें हम तक पहुंचाने वाले रिपोर्टर्स का दिल से धन्यवाद।

आप सभी को यह जान कर खुशी होगी की "परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र" का द्वितीय वार्षिकी समारोह अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में सम्पन्न किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सड़को को जाम और दुर्घटनाओं से मुक्त करवाने के साथ दिल्ली को प्रदूषण मुक्त राज्य का उद्देश्य रखा गया है। इस समारोह में निम्नलिखित मुद्दों पर वाद- विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा

1. लेन ड्राइविंग कितनी अनिवार्य?"
2. "सड़क दुर्घटना से कैसे हो सकता हैं बचाव ?"
3. "दिल्ली को कैसे प्रदूषण मुक्त राज्य बनाया जा सकता है?"

वाद- विवाद प्रतियोगिता में हिस्सेदारी लेने वाले वक्ताओं के वक्तव्य के साथ परामर्शदाताओं से चर्चा भी इस समारोह में रखी जा रही है। इसके साथ इस आयोजन में भारत देश में निर्मित ई वाहनो, वीएलटीडी संयंत्र, एवम् अन्य उपयोगी स्टाल भी सब को आकृषित करने के लिए उपलब्ध होंगे। इस समारोह में

1. सबसे अच्छा विचार / तर्क और समाधान प्रदान करने वाले वक्ता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
2. परिवहन क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले संगठनों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
3. सड़क सुरक्षा के प्रति कार्य करने वाले संगठनों के पदाधिकारियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
4. परिवहन विशेषज्ञों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
5. समाचार पत्र से अलग अलग राज्यों से जुड़े एंकर, वीडियो ग्राफर, रिपोर्टर्स, लेखक, ज्योताचार्य, कवि एवम् सहायकों को सम्मानित किया जाएगा।

संजय कुमार बाटला
संपादक

वायु प्रदूषण से इन वाहन मालिकों को ज्यादा नुकसान, काटे गए 31 हजार से अधिक चालान

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण पुराने वाहन हैं। GRAP के तीसरे और चौथे चरण के प्रतिबंध लगने पर BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर रोक लग जाती है। सर्दियों में AQI बढ़ने पर GRAP लागू होता है जिससे पुराने वाहन मालिकों को परेशानी होती है। DPCC के अनुसार GRAP प्रतिबंधों के दौरान 31 हजार से ज्यादा वाहनों का चालान किया गया।

नई दिल्ली । राजधानी में प्रदूषण के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर पुराने वाहनों पर पड़ रहा है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तीसरे और चौथे चरण के प्रतिबंध लगते ही बीएस तीन मानकों वाले पेट्रोल से चलने वाले वाहन और बीएस चार मानकों वाले डीजल से चलने वाले वाहनों पर रोक लग जाती है। अगर ये सड़कों पर नजर आते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

आमतौर पर मानसून को छोड़कर, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर ज्यादातर दिनों में सामान्य से ज्यादा रहता है। लेकिन, सर्दियों के दौरान स्थिति और भी खराब हो जाती है। इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को रोकने के लिए GRAP प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

AQI के 350 से ऊपर होने पर GRAP 3 प्रतिबंध लगाए जाते हैं और 400 से ऊपर होने पर GRAP 4 प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इस दौरान पुराने वाहन मालिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की हाल ही में जारी रिपोर्ट से पता चलता है कि सर्दियों के दौरान जीआरएपी प्रतिबंधों के मद्देनजर कितने वाहनों को निशाना बनाया गया।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी का कहना है कि वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के बजाय दिल्ली की खराब परिवहन व्यवस्था को सुधारना बेहतर होगा। अगर ऐसा संभव हुआ तो दिल्लीवासी निजी वाहनों का इस्तेमाल वैसे भी कम कर देंगे।

डीपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सर्दी के मौसम में कुल 42 दिन तक ग्रैप प्रतिबंध लगाए गए।

13 दिन तक ग्रैप 3 प्रतिबंध लगाए गए, जबकि 29 दिन तक ग्रैप 4 प्रतिबंध लगाए गए। इसके चलते पुराने इंजन वाली गाड़ियों को भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।

इस दौरान कुल 31 हजार 209 वाहनों का चालान किया गया।

वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर के बीच कुल चार लाख 52 हजार 833 वाहनों की जांच की गई।

49 हजार 484 ऐसे मालवाहक वाहन थे, जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं था, लेकिन वे यहां से गुजरना चाहते थे। ऐसे वाहनों को बाहर से ही वापस कर दिया गया।

दिल्ली के इस इलाके में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, काट डाले 800 से ज्यादा चालान; उठाए 80 वाहन

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने महिपालपुर सर्विस रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 800 चालान काटे और 80 वाहनों को जब्त किया। यह कार्रवाई NH-48 पर अवैध पार्किंग के कारण हो रही यातायात समस्या को दूर करने के लिए की गई। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इस अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही थी।

दिल्ली । नई दिल्ली रेंज की ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को महिपालपुर, सर्विस रोड, एनएच-48 पर अतिक्रमण के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत कुल 800 चालान विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चालान काटे गए। वहीं अवैध तरीके से खड़े करीब 80 वाहनों को क्रेन से उठाया गया है।

पुलिस उपायुक्त (यातायात) राजीव कुमार ने बताया कि महिपालपुर सर्विस रोड, जो दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, यह दिल्ली-गुरुग्राम और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के सभी टर्मिनलों को जोड़ती है। यह क्षेत्र वसंत विहार ट्रैफिक सर्कल के अधिकार क्षेत्र में आता है और यहां हर दिन हजारों लोगों का आना जाना होता है।

पैदल चलनेवाले लोगों को हो रही थी काफी दिक्कतें

इस दौरान वहां पर निरीक्षण करने पर अधिकारियों ने देखा कि सड़क के दोनों ओर अवैध रूप से पार्क किए गए आटो, निजी टैक्सी आदि के चलते सड़क संकरी हो गई है। इससे पैदल चलने वालों के साथ ही वाहन चालकों को काफी दिक्कत हो रही थी। अतिक्रमण के कारण इससे क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम भी हो रहा था। स्थिति का विश्लेषण करते हुए एसीपी साउथ वेस्ट और एसीपी नई दिल्ली के देखरेख में टीम बनाकर 13 अप्रैल को एक विशेष अभियान चलाया गया।

दोपहर से लेकर शाम करीब सात बजे चले अभियान में ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते गलत पार्किंग करने पर 310 चालान समेत कुल 800 चालान काटे गए। वहीं क्रेन से 80 गाड़ी उठाई गई। अधिकांश अतिक्रमण को मौके पर ही हटा दिया गया है।

नशा छोड़ो बोतल तोड़ो :- बिजेंद्र सैनी

परिवहन विशेष न्यूज

साईकिल चलाएगे पैडल मारते जायेगे नशे को दूर भगायेंगे

भारत देश को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी द्वारा 5 अप्रैल को हिसार से शुरू की गई साइक्लोथॉन नशा मुक्त हरियाणा के सामाजिक संदेश के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश को कवर करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों से होकर गुजरने वाली यह साइक्लोथॉन नशा मुक्त हरियाणा का संदेश देने में अहम रहेगी।

साईकिल रैली हिसार से चलकर आज फ़रीदाबाद पहुँची यहाँ फ़रीदाबाद के अन्य इलाकों गाँवों से होती हुई पाली फ़रीदाबाद से होकर गुरुग्राम तक लोगों को जागरूक करेगी

साइक्लोथॉन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा अपनी साइकिल के साथ लोटा और नमक लिए हुए चल रहे हैं जो एक मजबूत सामाजिक संकल्प का संकेत है। वे आमजन से लोटे में नमक डलवाते हुए अपने क्षेत्र सहित हरियाणा प्रदेश को 'नशा मुक्त हरियाणा' बनने का संकल्प दिलवा रहे हैं

फ़रीदाबाद में आज रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन की टीम ने नशा मुक्ति अभियान पोस्टरो द्वारा स्वागत करा और लोगो को संदेश दिया कि हमे नशे का त्याग करना चाहिए क्यूँकि नशे के कारण हमारा नौजवान ख़तरे में पड़ रहा है नशे के कारण कितने घर बर्बाद हो चुके हैं और नशा करने से बहुत जानलेवा बीमारी लग जाती हैं जिसके कारण जान माल की हानि हो जाती है कितने नोजवान नशे की हालत में वाहन को ग़लत तरीको से चलाते हैं और सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर 5000 का जुर्माना व सजा भी हो सकती है सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफ़िक नियमों का पालन करे पैदल यात्रियों का ख़ास ध्यान रखें ख़ुद भी सुरक्षित रहें दुसरो को भी सुरक्षित रहने दें हमे सप्ताह में कम से कम दो बार साईकिल जरुर चलानी चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और सडकों पर प्रदूषण के साथ ट्रैफिक जाम भी कम होगा और आपके धन की भी बचत होगी इसलिए साईकिल ज़रूर चलाए

आज इस नशा मुक्ति साईकिल अभियान में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल हरियाणा सरकार के सदस्य सरदार देवेंद्र सिंह, रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन से बिजेंद्र सैनी, सौरभ बिंदल, सुबोध नागपाल, सत्यवीर दहिया, नरेश शर्मा, नवीन कुमार, डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, एवं अन्य सदस्य मौके पर मौजूद थे।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती आज

बाबासाहेब अंबेडकर के नाम से मशहूर बीआर अंबेडकर एक अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था (देश के कुछ हिस्सों में उन्हें आज भी अछूत माना जाता है)। भारत के संविधान के प्रमुख निर्माता अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों की भी वकालत की। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में पहचाने जाने वाले अंबेडकर का भारतीय गणराज्य की संपूर्ण अवधारणा के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। देश के प्रति उनके योगदान और सेवा को सम्मान देने के लिए हर साल 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाया जाता है।

अम्बेडकर और उनके योगदान का संक्षिप्त इतिहास अंबेडकर कानून और अर्थशास्त्र के एक प्रतिभाशाली छात्र और व्यवसायी थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी मजबूत पकड़ का इस्तेमाल भारत को पुरातन मान्यताओं और विचारों से मुक्त करने के लिए किया। उन्होंने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने की अवधारणा का विरोध किया और सभी के लिए समान अधिकारों की वकालत की। उन्होंने " सामाजिक बहिष्कृत " जातियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसमें गैर-ब्राह्मण वर्ग के लोग शामिल थे। उन्होंने वंचित वर्गों के बारे में अधिक लिखने के लिए पाँच पत्रिकाएँ शुरू कीं- मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का कड़ा विरोध किया। लंबी चर्चा के बाद पिछड़े वर्गों की ओर से अंबेडकर और अन्य हिंदू समुदायों की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ता मदन मोहन मालवीय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पूना पैक्ट के नाम से मशहूर इस समझौते ने वंचित वर्ग के लोगों को विधानमंडल में 148 सीटें प्राप्त करने की अनुमति दी, जबकि ब्रिटिश सरकार ने 71 सीटें सुझाई थीं। इस वंचित वर्ग को बाद में भारतीय संविधान में " अनुसूचित जाति " और " अनुसूचित जनजाति " के रूप में मान्यता दी गई। ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद, अंबेडकर को पहला कानून और न्याय मंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें भारत के पहले संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और इस तरह भारत का संविधान अस्तित्व में आया।

डॉ. बी.आर.अम्बेडकर की शैक्षिक योग्यता डॉ. बी.आर. अंबेडकर भारतीय इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जिन्होंने शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की, जिनमें मुंबई में एलफिंस्टन कॉलेज, यूके में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूएसए में कोलंबिया विश्वविद्यालय शामिल हैं। उनकी सबसे उल्लेखनीय शैक्षणिक उपलब्धियों में से एक विदेशी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बनना था। इसके अलावा, उन्होंने दो साल तक मुंबई में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया, जहाँ उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल निचली जाति के छात्रों के अधिकारों की वकालत करने के लिए किया।

अम्बेडकर जयंती कैसे मनाई जाती है? बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है, खास तौर पर महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों और उन सभी समुदायों में जिनके लिए अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी। अंबेडकर की मूर्तियों और चित्रों पर माला चढ़ाकर लोग समाज सुधारक को श्रद्धांजलि देते हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी वर्ष 2016, 2017 और 2018 में अंबेडकर जयंती मनाई। इस दिन अंबेडकर के जीवन से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम और चर्चाएं आम बात हैं।

अंबेडकर का दर्शन आज भी प्रासंगिक है। भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था को आकार देने में बाबासाहेब की सक्रिय भूमिका के बिना, पुरानी और पुरातन मान्यताओं से आगे बढ़कर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देश की तरक्की करना लगभग असंभव होता।

अम्बेडकर जयंती क्यों मनाई जाती है? भारत में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, ताकि भारतीय गरीबों के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया जा सके और उनका सम्मान किया जा सके। भारतीय संविधान के पीछे उनका मुख्य दिमाग था। 1923 में, शिक्षा की आवश्यकता को फैलाने और निम्न आय वर्ग की वित्तीय स्थिति को समृद्ध करने के लिए उनके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। देश में जातिवाद को खत्म करने के उद्देश्य से उनके द्वारा एक सामाजिक आंदोलन चलाया गया था। उन्होंने पुजारी विरोधी आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन आदि जैसे सामाजिक आंदोलन शुरू किए। 1930 में नासिक में मानव अधिकारों के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था। उनके अनुसार, राजनीतिक सत्ता के माध्यम से दलितों की समस्याओं का पूरी तरह से समाधान नहीं होता। दलितों को समाज में समान अधिकार दिए जाने चाहिए। 1942 में वे विक्टोरिया की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। वे जीवन भर समाज सुधारक और अर्थशास्त्री रहे।

डॉ. बी.आर.अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान डॉ. बी.आर. अंबेडकर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कई कार्यक्रमों के माध्यम से दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। इनमें समानता जनता, मूक नायक आदि उल्लेखनीय कार्यक्रम शामिल हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश ब्रिटिश प्रशासन से मुक्त हुआ तो कांग्रेस सरकार ने उन्हें पहला कानून मंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया था। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने देश के लिए नया संविधान तैयार किया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को नया संविधान अपनाया था।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक है, की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि वे एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने तीन किताबें लिखीं: "रुपये की समस्या: इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान," "ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त," और "ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास।" चूंकि डॉ. बी.आर. अंबेडकर एक अर्थशास्त्री थे, इसलिए उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को कृषि क्षेत्र और औद्योगिक गतिविधियों के विकास के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को बेहतर शिक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रेरित किया। दलित बौद्ध आंदोलन उनसे प्रेरित था।

शुगर के लिए प्राकृतिक उपाय – अँटॉक्स D और अँटॉक्स T!

मधुमेह (डायबिटीज) को नियंत्रित करने के लिए यह न्यूट्रिशनल फॉर्मूले पैंक्रियास के कार्य में सुधार करते हैं।

1 अँटॉक्स D (अर्क):

- पूरी तरह से प्राकृतिक औषधीय पौधों का अर्क।
- शरीर में पोषण की कमी को पूरा करता है।
- पैंक्रियास को सक्रिय कर प्राकृतिक इंसुलिन उत्पादन में मदद करता है।
- बीटा-सेल्स को मजबूत करता है और उनका उत्पादन बढ़ाता है।
- इंसुलिन या शुगर की गोलियों की आवश्यकता को कम करने में मदद करता है।

2 अँटॉक्स T (काढ़ा):

- शरीर से विषाक्त पदार्थों को कम करता है।
- रक्त को पतला करके इंसुलिन सिक्रेशन को सुधारता है।
- अन्य अंगों का संरक्षण करता है और शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है।
- थकान को कम करता है और शरीर के प्राकृतिक कार्यों को सुधारता है।

यह कैसे फायदेमंद है?

- शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है।
- वजन और रक्तदाब (BP) को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
- शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है और धीरे-धीरे दवाइयों पर निर्भरता कम होती है।

आहार, योग, व्यायाम और सही जीवनशैली से मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है।

अब शुगर पर विजय प्राप्त करें – प्राकृतिक, सुरक्षित, और प्रभावी!

बड़े से बड़े पथरी को गलाकर बाहर निकालने के लिए आजमाएं पांच तरह के घरेलू उपचार

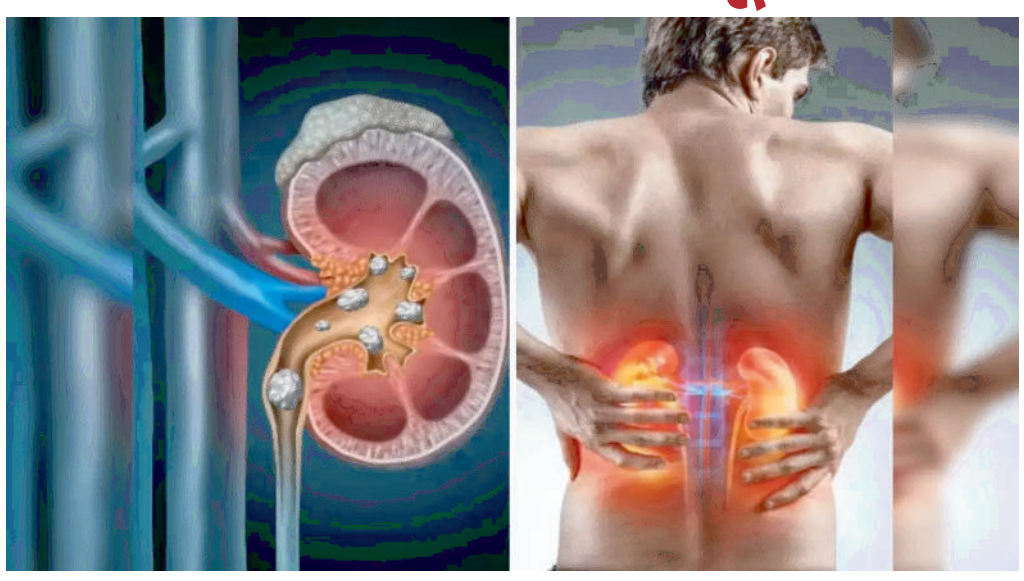

मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। किडनी का मुख्य काम शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना और पानी, अन्य तरल पदार्थ, रासायनिक और खनिज के स्तर को बनाए रखना है। यह शरीर में खून को भी फिल्टर करती है। स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्ति के पास ठीक से काम करने वाली किडनी होनी चाहिए। मनुष्य रोजाना विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करता है, जो बाद में ऊर्जा में बाल जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कई तरह के विषाक्त पदार्थ शरीर में जमा होते रहते हैं। ऐसे जहरीले पदार्थों का जमा होना मानव शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। शरीर में पानी की कमी से गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन (kidney stones) बन सकती हैं। ये पत्थर या तो मटर के आकार के हो सकते हैं या गोल्फ की गेंद जितने बड़े हो सकते हैं। पथरी आमतौर पर कैल्शियम ऑक्सालेट और कुछ अन्य यौगिकों से बने होते हैं और इनकी बनावट क्रिस्टल होती है।

किडनी की पथरी के लक्षण....

गुर्दे की पथरी बनने से वजन कम होने, बुखार, मतली, रक्तमेह और पेट के निचले हिस्से में गंभीर दर्द के साथ पेशाब करने में परेशानी हो सकती है। गुर्दे की पथरी ज्यादातर सर्जरी द्वारा हटा दी जाती है। लेकिन कुछ प्रभावी और प्राकृतिक तरीके हैं जिनके जरिए किडनी की पथरी को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है।

खूब पानी पिएं.....

जल को जीवन का अमृत माना गया है। यह हाइड्रेशन के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। पानी गुर्दे को खनिजों और पोषक तत्वों को भंग करने में मदद करता है, और पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया को तेज करता है। पानी शरीर से अनावश्यक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है जिससे किडनी को और नुकसान हो सकता है। जिन लोगों को गुर्दे की पथरी है उन्हें इन पत्थरों को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने के लिए दिन में 7-8 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है।

नींबू का रस और जैतून का तेल.

Harvard Health के अनुसार, नींबू के रस और जैतून के तेल का मिश्रण सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन यह किडनी की पथरी को शरीर से बाहर निकालने का एक बहुत ही प्रभावी घरेलू उपाय साबित हो सकता है। जो लोग अपनी किडनी से पथरी को प्राकृतिक रूप से हटाना चाहते हैं उन्हें इस तरल को रोजाना तब तक पीना चाहिए जब तक कि पथरी निकल न जाए। जबकि नींबू का रस गुर्दे की पथरी को तोड़ने में मदद करता है, जैतून का तेल बिना किसी समस्या या जलन के सिस्टम से गुजरने के लिए लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करता है।

सेब का सिरका....

सेब के सिरके में साइट्रिक एसिड होता है जो किडनी स्टोन को छोटे-छोटे कणों में तोड़ने और घुलने की प्रक्रिया में मदद करता है। यह मूत्रमार्ग के माध्यम से गुर्दे की पथरी को हटाने में मदद करता है। सेब के सिरके का सेवन विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और किडनी को भी साफ करने में मदद करता है। दो बड़े चम्मच सेब का सिरका रोजाना गर्म पानी के साथ तब तक लिया जा सकता है जब तक कि किडनी से पथरी पूरी तरह से निकल न जाए।

अनार का रस....

नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, अनार कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अनार का रस सबसे अच्छे प्राकृतिक पेय में से एक है जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। यह गुर्दे की पथरी को प्राकृतिक रूप से दूर करने में मदद करता है। इसमें अच्छे एंटीऑक्सिडेंट होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करते हैं।

आयुर्वेद अपनाएं स्वस्थ जीवन पाए

सूतक/पातक विचार

हमारे ऊपर आ रहे कष्टो का एक कारण सूतक के नियमो का पालन नहीं करना भी हो सकता है।

सूतक का सम्बन्ध "जन्म एवं मृत्यु के" निम्मित से हुई अशुद्धि से है ! जन्म के अवसर पर जो ₹₹नाल काटा₹₹ जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया में अन्य प्रकार की जो हिंसा होती है, उसमे लगने वाले दोष/पाप के प्रायश्चित स्वरुप "सूतक" माना जाता है !

जन्म के बाद नवजात की पीढ़ियों को हुई अशुचिता

पीढ़ी तक – १० दिन
४ पीढ़ी तक – १० दिन
५ पीढ़ी तक – ६ दिन

ध्यान दें :- एक रसोई में भोजन करने वालों के पीढ़ी नहीं गिनी जाती ' वहाँ पूरा १० दिन का सूतक माना है !

प्रसूति (नवजात की माँ) को ४५ दिन का सूतक रहता है।

प्रसूति स्थान १ माह तक अशुद्ध है ! इसीलिए कई लोग जब भी अस्पताल से घर आते हैं तो स्नान करते हैं !

अपनी पुत्री
पीहर में जनै तो हमे दिन का,
ससुराल में जन्म दे तो उन्हें १० दिन का सूतक रहता है ! और हमे कोई सूतक नहीं रहता है !

नौकर-चाकर
अपने घर में जन्म दे तो १ दिन का,
बाहर दे तो हमे कोई सूतक नहीं !

पालतू पशुओं का
घर के पालतू गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी इत्यादि को घर में बच्चा होने पर हमे १ दिन का सूतक रहता है !

किन्तु घर से दूर-बाहर जन्म होने पर कोई सूतक नहीं रहता !

बच्चा देने वाली गाय, भैंस और बकरी का दूध, क्रमशः १५ दिन, १० दिन और ८ दिन तक "अभक्ष्य/अशुद्ध" रहता है !

पातक

पातक का सम्बन्ध "मरण के" निम्मित से हुई अशुद्धि से है ! मरण के अवसर पर ₹₹दाह-संस्कार₹₹ में इत्यादि में जो हिंसा होती है, उसमे लगने वाले दोष/पाप के प्रायश्चित स्वरुप "पातक" माना जाता है !

मरण के बाद हुई अशुचिता :-
पीढ़ी तक – १२ दिन
४ पीढ़ी तक – १० दिन
५ पीढ़ी तक – ६ दिन

ध्यान दें :- जिस दिन ₹₹₹दाह-संस्कार₹₹ किया जाता है, उस दिन से पातक के दिनों की गणना होती है, न कि मृत्यु के दिन से ! यदि घर का कोई सदस्य बाहर/विदेश में है, तो जिस दिन उसे सूचना मिलती है, उस दिन से शेष दिनों तक उसके पातक लगता है ! अगर १२ दिन बाद सूचना मिले तो स्नान-मात्र करने से शुद्धि हो जाती है !

गर्भपात

किसी स्त्री के यदि गर्भपात हुआ हो तो, जितने माह का गर्भ पतित हुआ, उतने ही दिन का पातक मानना चाहिए। घर का कोई सदस्य ₹₹तपस्वी' साधु सन्यासी₹₹₹ बन गया हो तो, उस साधु सन्त को , उसे घर में होने वाले जन्म-मरण का सूतक-पातक नहीं लगता है ! किन्तु स्वयं उसका ही मरण हो जाने पर उसके घर वालों को १ दिन का पातक लगता है !

विशेष

किसी अन्य की शवयात्रा में जाने वाले को १ दिन का, मुर्दा छूने वाले को दिन और मुर्दे को कन्धा देने वाले को ८ दिन की अशुद्धि जाननी चाहिए !

घर में कोई ₹आत्मघात ₹करले तो ६ महीने का पातक मानना चाहिए ! यदि कोई स्त्री अपने पति के मोह/निर्मोह से₹आग लगाकर जल मरे,₹ बालक पढाई में फेल होकर या कोई अपने ऊपर दोष देकर ₹आत्महत्या₹ कर मरता है तो इनका पातक बारह पक्ष याने ६ महीने का होता है ! उसके अलावा भी कहा है कि जिसके घर में इस प्रकार ₹अपघात₹ होता है, वहाँ छह महीने तक कोई बुद्धिमान मनुष्य भोजन अथवा जल भी ग्रहण नहीं करता है ! वह मंदिर नहीं जाता और ना ही उस घर का द्रव्य मंदिर जी में चढ़ाया जाता है ! जहां आत्महत्या हुई है, उस घर का पानी भी ६ माह तक नहीं पीना चाहिए। एवं अनाचारी स्त्री-पुरुष के हर समय ही पातक रहता है।

यह भी ध्यान से पढ़िए

सूतक-पातक की अवधि में "देव-शास्त्र-गुरु" का पूजन, प्रक्षाल, आहार आदि धार्मिक क्रियाएं वर्जित होती हैं ! इन दिनों में मंदिर के उपकरणों को स्पर्श करने का भी निषेध है ! यहाँ तक की गुल्लक में रुपया डालने का भी निषेध बताया है ! दान पेटी मे दान भी नहीं देना चाहिए। देव-दर्शन, प्रदिक्षणा, जो पहले से याद हैं वो विनती/स्तुति बोलना, भाव-पूजा करना, हाथ की अँगुलियों पर जाप देना शास्त्र सम्मत है ! कहीं कहीं लोग सूतक-पातक के दिनों में मंदिर ना जाकर इसकी समाप्ति के बाद मंदिरजी से गंधोदक लाकर शुद्धि के लिए घर-दुकान में छिड़कते हैं, ऐसा करके नियम से घोनघोर पाप का बंध करते हैं ! मानो या न मानो,

यह सत्य है, नहीं मानने पर दुःख, कष्ट, तकलीफ, होगी

इन्हे समझना इसलिए ज़रूरी है, ताकि अब आगे घर-परिवार में हुए जन्म-मरण के अवसरों पर अनजाने से भी कहीं दोष का उपार्जन ना हो।

कानपुर में 3 दिन के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत : कड़ी सुरक्षा

सुनील बाजपेई

कानपुर। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज रविवार से 3 दिन के लिए 17 अप्रैल तक कानपुर में ही प्रवास करेंगे। इस दौरान सुरक्षा के भी इंतजाम बेहद रखे गए हैं। यहां कारवालो नगर के संघ कार्यालय केशव भवन में कड़ी सुरक्षा के साथ ही उनके भव्य स्वागत की भी तैयारी पहले ही की जा चुकी हैं।

संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस तीन दिवसीय प्रवास के दौरान केशव भवन के चौतरफा और रूफ टॉप सिक्योरिटी रहेगी। इसके साथ ही सिर्फ सूची में शामिल या पास धारकों को ही केशव भवन में प्रवेश मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक दिन पहले पुलिस कमिश्नर और एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने मौका मुआयना किया।

इस बारे में यहां के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने केशव भवन में ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ब्रीफिंग की। इस दौरान केशव भवन के बाहर से लेकर अंदर तक और रूफ टॉप सिक्योरिटी व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही चौतरफा सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी। सभी प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर और बगैर पास के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केशव भवन को आरएसएस चीफ के रहने तक हाई सिक्योरिटी जोन में बदला गया है। इसके साथ ही प्रांत प्रचारक श्री राम जी के साथ भी अफसरों ने बैठक की और सिक्योरिटी को लेकर चर्चा की। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण आयोजनों में भी शामिल होंगे।

मनुष्य की बुद्धि, प्रिज्य की भांति काम करती है और चीजों को तोड़ती है। जब तक हम बुद्धि को हटाकर देखने की कला न पैदा कर पायें, तब तक हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा, चीजें टूटी हुई, अनेक रंगों में दिखाई पड़ेगी।

अगर इस प्रिज्य को हटा लें, तो चीज एक रंग की हो जाती है, यानि सफेद हो जाती है। ध्यान रहे कि सफेद कोई रंग नहीं है। सफेद सब रंगों का जोड़ है। सफेद में सब रंग छिपे हैं। इसलिए स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है जिससे एक छोटा-सा चाक बना लेते हैं। चाक में सात रंगों की पंखुड़ियां लगा देतें हैं। और फिर चाक को जोर से घुमाते हैं। चाक जब जोर से घूमता है, तो सात रंग नहीं दिखाई पड़ते, चाक सफेद रंग का दिखाई पड़ने लगता है। सफेद सातों रंगों का जोड़ है। सातों रंग सफेद के टूटे हुए हिस्से हैं। जगत इंद्रधनुष है। इंद्रियों से टूटकर जगत का इंद्रधनुष निर्मित होता है। यदि इंद्रियों को हटा दें, मन को हटा दें, बुद्धि को हटा दें, तो सारा जगत शुभ्र, एक रंग का हो जाता है। वहां सभी विरोध मिल/विलीन हो जाते हैं। वहां काला, हरा, लाल, पीला, सब रंग एक हो जाते हैं। गीता में भगवान श्रीकृष्ण जो कह रहे हैं वह सभी विरोधाभास जो इंद्रधनुष की भांति दिखाई पड़तें हैं, को मिटाने वाली बातें हैं। वह कहतें हैं कि निर्गुण भी वहीं हैं, सगुण भी वहीं हैं, सब गुण उन्हीं के/से पैदा हो रहें हैं और उन्हीं में समा रहें हैं। फिर भी कोई गुण/रंग उनका नहीं है। वह सभी गुणों/रंगों से विरक्त/रिक्त हैं।

सारसों की कमी पर्यावरणीय असंतुलन का नतीजा या कुछ और?

राजेश खण्डेलवाल

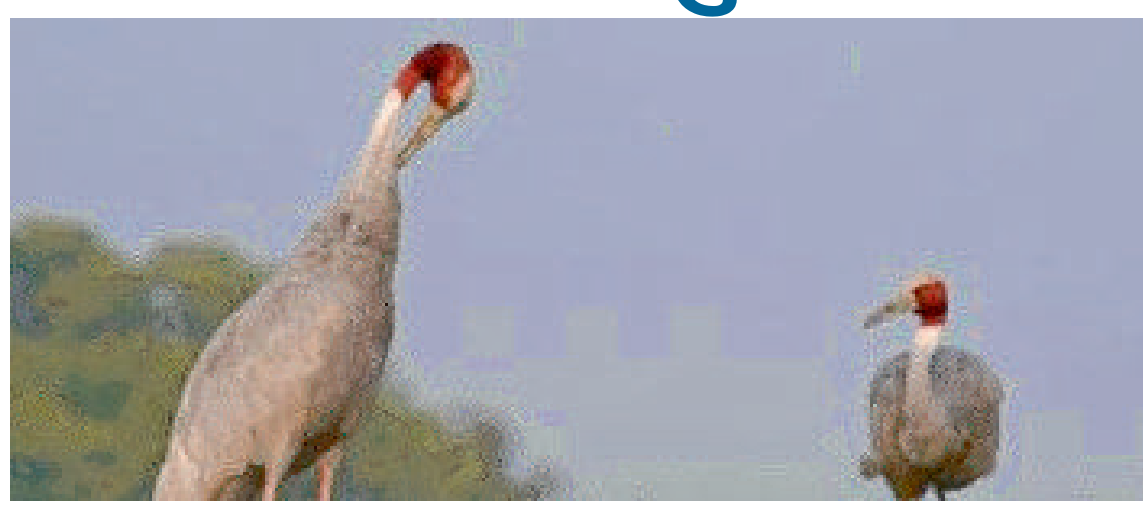

भरतपुर जिले में सारसों की संख्या में भारी कमी पर्यावरणीय असंतुलन का नतीजा है या कुछ और? इस सवाल ने पर्यावरणविद और वन्यजीव प्रेमियों को चिंतित कर दिया है। हाल ही हुई 42वीं सारस गणना के मुताबिक भरतपुर जिले में इस बार सारसों की संख्या घटकर 79 रह गई है, जबकि पिछले साल यह संख्या 143 थी। विशेषज्ञ इसे आद्रभूमियों के सिकुडने, जल स्रोतों की कमी और बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप से जोडकर देख रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि इस बार बरसात अधिक होने से सारस पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश में पलायन कर गए हैं। अगर सारसों के अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनी तो आने वाले वर्षों में इनकी संख्या में और गिरावट आ सकती है।

घना केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी व वन विभाग के संयुक्त प्रयास से 10 फरवरी को 42वीं सारस गणना शुरू हुई। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 14 सारस मिले, जबकि पूरे भरतपुर जिले में मात्र 79 सारस ही देखे गए। सारसों की गणना के लिए जिले को 17 जोन में विभाजित कर 17 टीमों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया। इसमें महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र और वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधार्थी छात्र-छात्राओं, वन्यजीव प्रेमियों, नेचर गाइड्स, रिक्शा चालकों और वन विभाग के कर्मियों सहित 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया। सोसायटी के अध्यक्ष एडवोकेट कृष्ण कुमार बताते हैं कि इस बार सारस गणना अप्रेल की बजाए फरवरी में की गई, जिससे भी संख्या में बदलाव देखने को मिला। इस साल अच्छी बरसात के कारण कई स्थानों पर जलभराव हुआ है, जिससे सारसों को भरतपुर में सीमित रहने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई और वे पास के उत्तर प्रदेश क्षेत्र की ओर पलायन कर गए। हालांकि अप्रेल तक इनकी संख्या में इजाफा होने की संभावना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सारसों की संख्या में गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं। भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों में जल स्रोतों की कमी सारसों के आवास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान समेत कई आद्रभूमियां पानी की कमी से जूझ रही हैं, जिससे सारसों का प्रवास प्रभावित हुआ है। इस बार मानसून बेहतर रहने के कारण कई जलाशयों और आद्रभूमियों में पानी भरा हुआ है। इसके चलते सारसों को भरतपुर में स्थायी रूप से रहने की जरूरत नहीं पड़ी और वे पास के उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। शहरीकरण, खेती में बदलाव और जल स्रोतों पर अतिक्रमण सारसों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर रहे हैं। अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान से आद्रभूमियों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे सारसों को अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा। कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से सारसों के लिए उपलब्ध भोजन की मात्रा भी प्रभावित हुई है।

इन समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों ने कई उपाय सुझाए हैं। गणना के समन्वयक अनंत कुमार शर्मा बताते हैं कि सारसों के संरक्षण के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। आद्रभूमियों और जल स्रोतों की रक्षा की जाए और जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाया जाए ताकि कीटनाशकों का दुष्प्रभाव कम हो सके। इसके साथ ही, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के क्षेत्रों में मानवीय दखल को नियंत्रित किया जाए ताकि सारस के प्राकृतिक आवास को बचाया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार सारस की घटती संख्या एक गंभीर चिंता का विषय है और इसके संरक्षण के लिए प्रशासन, वन विभाग और स्थानीय समुदाय को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है. सारस के प्राकृतिक आवासों की रक्षा नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में इनकी संख्या में और गिरावट आ सकती है, जिससे यह दुर्लभ पक्षी संकट में आ सकता है।

(लेखक लाडली मीडिया अवार्डी व स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

क्या आरएसएस मंदिर मस्जिद विवाद का समर्थन नहीं करता ?

रामस्वरूप रावतसरे

भारत में ऐसा कोई शहर नहीं बताया जाता जहां मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा सामने न आए। इस विवाद को लेकर हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इससे चिंतित दिखाई दे रहा है। आरएसएस ने पहले अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे बड़े मंदिर-मस्जिद विवादों में ही हिंदू पक्ष के दावों का समर्थन किया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कई बार मस्जिदों के नीचे मंदिरों की खोज को रोकने की अपील की है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भी इसी तरह की चिंता जताई है। इससे यह स्पष्ट है कि संध नहीं चाहता कि यह विवाद आगे चलकर किसी विकट समस्या का कारण बने।

होसबाले के अनुसार कि अगर हम 30,000 मस्जिदों को खोदना शुरू कर दें, यह दावा करते हुए कि वे मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं तो भारत किस दिशा में जाएगा? क्या इससे समाज में और अधिक शत्रुता और नाराजगी नहीं पैदा होगी? क्या हमें एक समाज के रूप में आगे बढ़ना चाहिए या अतीत में फंसे रहना चाहिए? कथित तौर पर नष्ट किए गए मंदिरों को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें इतिहास में कितना पीछे जाना चाहिए?'' शताब्दी वर्ष के मौके पर हुए एक इंटरव्यू में होसबाले ने कई विषयों पर संगठन के विचार स्पष्ट किए। इनमें से कई विचार भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े अन्य संगठनों के विचारों से मेल नहीं खाते हैं।

मस्जिदों के नीचे मंदिरों की खोज पर होसबाले ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन आरएसएस ने शुरू नहीं किया था। आरएसएस के स्वयंसेवक सांस्कृतिक महत्व के कारण इस आंदोलन में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, ''उस समय, विश्व हिंदू परिषद और धार्मिक नेताओं ने तीन मंदिरों का उल्लेख किया था। अगर कुछ आरएसएस स्वयंसेवक इन तीन मंदिरों को फिर से प्राप्त करने के प्रयासों में शामिल होना चाहते थे, तो आरएसएस ने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन अब स्थिति बहुत अलग है। देश में 30,000 मस्जिदों के नीचे मंदिरों के दावे हैं। अगर हम इतिहास को पलटने के लिए उन सभी को खोदना शुरू कर दें तो क्या इससे समाज में और अधिक दुश्मनी और नफरत नहीं पैदा होगी?''

होसबाले ने कहा कि मस्जिदों के नीचे मंदिरों की खोज करने से हम अस्पृश्यता को खत्म करने, युवाओं में जीवन मूल्यों को स्थापित करने, संस्कृति की रक्षा करने और भाषाओं को संरक्षित करने जैसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने कहा, ''जब मंदिरों की बात आती है, तो क्या किसी इमारत में जो अब एक मस्जिद है, कोई दिव्यता है? क्या हमें इमारत में हिंदू धर्म की तलाश करनी चाहिए, या हमें उन लोगों में हिंदू धर्म को जगाना चाहिए जो खुद को हिंदू नहीं मानते हैं? इमारतों में हिंदू धर्म के अवशेषों की खोज करने के बजाय अगर हम समाज में हिंदू धर्म की जड़ों को जगाते हैं तो मस्जिद का मुद्दा अपने आप हल हो जाएगा।''

होसबाले ने दावा किया कि भारत में लोग एक ही नस्ल के हैं और हिंदू धर्म अनिवार्य रूप से मानवतावाद है। भारतीय मुसलमानों ने अपनी धार्मिक प्रथाओं को बदल दिया होगा, लेकिन उन्हें अपनी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। यह आरएसएस का रुख है।'' हालांकि, उन्होंने कहा कि मुसलमानों या ईसाइयों को हिंदू होने के लिए अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ''हमें दूसरों की पूजा के तरीकों से कोई विरोध नहीं है, जब तक कि यह इस देश की संस्कृति के खिलाफ न हो।''

होसबाले के अनुसार आएसएस ने हमेशा शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनी मातृभाषा को बढ़ावा दिया है। हम मानते हैं कि बच्चों के लिए सीखना आसान और अधिक स्वाभाविक है जब उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने को न केवल एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में देखा जाना चाहिए बल्कि संस्कृतियों को संरक्षित करने के साधन के रूप में भी देखा जाना चाहिए। अंग्रेजी के प्रति आकर्षण समझ में आता है। लेकिन हमें एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है।''

होसबाले ने ऐसी आर्थिक योजनाएं बनाने का भी आह्वान किया जो क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षित लोगों के लिए नौकरियां प्रदान करें। उन्होंने कहा, ''बुजुर्गों, न्यायाधीशों, शिक्षा विशेषज्ञों, लेखकों, राजनेताओं और धार्मिक नेताओं को इस पर सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। तीन-भाषा फॉर्मूले का उचित कार्यान्वयन 95 प्रतिशत समस्या का समाधान कर सकता है। समस्याएं तब पैदा होती हैं जब भाषा का राजनीतिकरण किया जाता है। हमारे देश ने हजारों वर्षों से भाषाई विविधता के भीतर एकता बनाए रखी है।''

होसबाले इसे गलत है कि किसी विशेष राजनीतिक समूह से संबंधित लोगों को देशभक्त के रूप में पहचाना जाए और दूसरों को गद्दार कहा जाए। देशभक्ति और राष्ट्रवाद सामान्य लक्षण हैं। उन्होंने कहा, देश में कई राजनीतिक दलों का अस्तित्व इसकी एकता में बाधा नहीं है। हालांकि, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से, हम सभी को कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।'' होसबाले से पूछा गया कि क्या आरएसएस का केवल एक राजनीतिक दल का समर्थन करना एक समस्या है। उन्होंने कहा कि यह मानना गलत है कि आरएसएस केवल एक राजनीतिक दल का समर्थन करता है। उन्होंने कहा, ''स्वयंसेवक किसी भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वयंसेवक स्वाभाविक रूप से उन दलों के साथ जुड़ते हैं जिनके आरएसएस के साथ संबंध हैं। अन्य दलों के स्वयंसेवकों को आरएसएस और उनकी पार्टी दोनों का हिस्सा बनने की अनुमति देनी चाहिए।''

उन्होंने कहा कि आरएसएस के स्वयंसेवकों के अल्पसंख्यकों, जाति, एकता, धर्मांतरण और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर कुछ विश्वास हैं, जो उनके लिए ऐसी पार्टी में काम करना मुश्किल बना देंगे जो इन सिद्धांतों के खिलाफ है। जबकि कई राजनीतिक दलों ने खुले तौर पर आरएसएस के साथ संपर्क में नहीं रहने का विकल्प चुना, संगठन ने दलों के नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखा है।'' होसबोले के अनुसार आरएसएस ने बार-बार कहा है कि वह राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहता है। हालांकि, जैसे-जैसे समय बदलता है, हमें अनुकूल होना चाहिए।''

आरएसएस पर उच्च जातियों के लोगों का पक्ष लेने का आरोप लगाये जाने को लेकर होसबाले ने कहा कि जबकि संगठन में सभी धर्मों और जातियों के लोग हैं। आरएसएस में जाति और धर्म पर चर्चा नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि संगठन में दिया जाने वाला पहला सबक यह है कि हम सभी हिंदू हैं और यह जाति द्वारा बनाए गए विभाजनों को कम करने के लिए किया जाता है।

होसबाले ने ''अखंड भारत'' पर आरएसएस के विचार को लेकर कहा कि जिसमें पड़ोसी देशों का क्षेत्र भी शामिल है, अपरिवर्तित हैं। उनके अनुसार हालांकि, हमें वैश्विक भू-राजनीति में बदलावों पर भी विचार करना चाहिए। ''अखंड भारत'' का सपना भारत के भीतर एक मजबूत और एकजुट हिंदू समाज के बिना साकार नहीं किया जा सकता है। जब भारत और हिंदू समाज अपनी ताकत दिखाएंगे, तो दुनिया इसे पहचानेगी।''

आरएसएस सहकार्यवाह के अनुसार संगठन का प्राथमिक उद्देश्य सभी का उत्थान और कल्याण है। इसे राम राज्य या धर्म राज्य कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के ''सर्वाच्च गौरव'' में होने के कुछ संकेतक हैं- जब अस्पृश्यता का उन्मूलन हो जाए। जब राष्ट्रवाद जीवन के सभी पहलुओं में व्यक्त किया जाए। जब सभी की भोजन, ज्ञान और शिक्षा तक पहुंच हो। जब सभी को सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा उपलब्ध हो। जब लिंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। जब भारत को किसी भी बाहरी आक्रमण - भौगोलिक या सांस्कृतिक - को रोकने की ताकत मिले। जब भारत को दुनिया के किसी भी हिस्से, देश या समाज को संकट में मदद करने की ताकत मिले। उन्होंने कहा, ''एक ऐसा वातावरण बनाना जहां हिंदू गर्व से खुद को हिंदू के रूप में पहचान सकें, इस दृष्टि का हिस्सा है।''

सौरभ भारद्वाज बतायें कि आतिशी मार्लेना के मुख्य मंत्री कार्यकाल में एक भूपेंद्र चौबे अकसर मुख्य मंत्री कार्यालय में क्यों दिखते थे : वीरेन्द्र सचदेवा

मुख्य संवाददाता/सुषमा रानी

नईदिल्ली : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की हमने तो पहले ही कहा है की आतिशी एवं सौरभ भारद्वाज में पार्टी कंट्रोल की पावर रेस चल रही और दोनों आगे पीछे एक ही विषय पर बोलते हैं और आज यह स्थापित हो गया।

पूर्व मुख्य मंत्री आतिशी मार्लेना ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिख कर वर्तमान मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता एवं उनके पति पर एक ओछा तंज कसा था जिसका हमारी पार्टी ने करारा जवाब दिया।

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की मेरे आलावा दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा एवं भाजपा मीडिया प्रमुख ने आतिशी की सोशल मीडिया पोस्ट की निंदा करते हुए ₹आप₹ सरकार के दौरान सुनीता केजरीवाल एवं भूपेंद्र चौबे आदि से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे जिसके बाद आतिशी मार्लेना से जवाब देते नही बना और जानकारी अनुसार विदेश चली गई हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की आश्चर्यजनक है की कल जिन ओछे सवालों पर कल आतिशी मार्लेना ने मुंह की खाई आज वो ओछे सवाल लेकर ₹आप₹ के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज सामने आये हैं।

सचदेवा ने कहा है की हमने कल भी कहा और आज फिर दोहराते हैं की दिल्ली की मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सेवा एवं श्रम से दिल्ली वालों का दिल जीता है और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ सचिव एवं अध्यक्ष से लेकर 3 बार पीतमपुरा से निगम पार्षद और अब मुख्य मंत्री पद तक का सफर पूरा किया है।

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा की हमने कल भी कहा और आज फिर दोहराता हूं की जनता की दैनिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए जनप्रतिनिधियों के परिजनों और पार्टी के प्रमुख पदधिकारियों का मिलना बात करना सामान्य बात है।

आप के दिल्ली मुखिया जो आज मुख्य मंत्री के पति के अधिकारियों से मिलने पर सवाल कर रहे हैं वह उनके नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा डिग्री घोटाले में फंसे मंत्री जितेंद्र तोमर की पत्नी को विधायक चुनवाने पर कोई प्रतिक्रिया देंगे ?

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की वैसे तो इस संदर्भ में हम चाहते हैं की अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना एवं सौरभ भारद्वाज हमारे द्वारा कल उठाये सवालों का जवाब दे पर अगर वह सब उनका जवाब नही देना चाहते तो सौरभ भारद्वाज मेरे दो सीधे सरल प्रश्नों का जवाब दे दें :

1. क्या यह सच नही की केजरीवाल सरकार में अधिकारियों को उनकी पत्नी को मैडम सी.एम. कहने के निर्देश थे और वह सरकारी फाइलों में उन्हे मैडम सी.एम. ही लिखते थे ? अगर यह सच नही तो सौरभ भारद्वाज बतायें की केजरीवाल ने फाइलों में अपनी पत्नी को सी.एम. मैडम लिखने वाले अधिकारियों पर कभी कोई कार्रवाई क्यों नही की ?

2. कृप्या दिल्ली वालों को बतायें की आतिशी मार्लेना के मुख्य मंत्री कार्यकाल में एक भूपेंद्र चौबे अकसर मुख्य मंत्री कार्यालय या आवास में क्यों दिखते थे ? क्या श्री चौबे पूर्व मुख्य मंत्री के रिश्तेदार हैं और हैं तो हर वक्त उनके कार्यालय या आवास में क्यों दिखते थे ?

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की हम मानते हैं की राजनीति सेवा का माध्यम है पर खेदपूर्ण है की ₹आप₹ नेताओं ने सत्ता के दौरान भी राजनीति को केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रखा और आज जब विपक्ष में हैं तो भी राजनीतिक विमर्श का स्तर गिराने में लगे हैं।

अपनी जन्मस्थली पर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करना मेरा सौभाग्य : वीरेन्द्र सचदेवा

मुख्य संवाददाता/सुषमा रानी

नई दिल्ली : भारत रत्न बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर के जयंति से एक दिन पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग एवं दुष्यंत कुमार गौतम की उपस्थिति में आज दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने अपनी जन्मस्थली क्षेत्र काली मस्जिद डीडीए फ्लैट्स (सीताराम बाजार वार्ड) में 'रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा स्थापित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया।

इस मौके पर एसोसिएशन अध्यक्ष नरेश कुमार, पूर्व विधायक राजकुमार आनंद, पूर्व पार्षद राकेश कुमार, प्रदेश भाजपा के सह-कार्यालय मंत्री अमित गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी और स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित थे।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरूण चुघ एवं दुष्यंत गौतम ने उपस्थित जनों को बाबा साहेब के विचारों और उनके योगदान को स्मरण कराते हुए उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प दिलाया और कहा की बाबा साहेब के स्मरण मात्र से हम में समाजिक चेतना आती है।

उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनसे स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की और फिर अपने पैतृक स्थल जहां उनका जन्म हुआ, वहां भी जाकर समय बिताया और अपने पुराने दिनों को याद किया।

वीरेन्द्र सचदेवा ने इस मौके पर कहा कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने अपने जन्म स्थल पर एक ऐसे महान व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण किया है जो समाजिक न्याय और एकता के प्रतिक हैं।

सचदेवा ने कहा कि डॉ. अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक न्याय, समानता और सम्मान के प्रतीक हैं। यह प्रतिमा हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि एक बेहतर और समावेशी समाज की नींव उच्च विचारों और संघर्ष से पड़ती है। हम उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह पहल न केवल श्रद्धांजलि है, बल्कि समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास भी है — जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले।

उद्देश्य के लिए दौड़: वैसाखी मैराथन में फिटनेस और नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए दिल्ली हुई एकजुट

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली ! विश्व पंजाबी संगठन और सन फाउंडेशन ने डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी, सांसद, राज्यसभा के संरक्षण में, नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में 'वैसाखी सुपरसिख 5K मैराथन' के तीसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सभी आयु समूहों के 3000 से अधिक नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिन्होंने "नशे को न कहें और फिट इंडिया" थीम के साथ वैसाखी के जीवंत त्योहार को मनाया।

डॉ. साहनी ने कहा कि फिट इंडिया के संदेश को अपनाने में नागरिकों का इतना जबरदस्त उत्साह देखना बहुत आनंदवर्धक है। वैसाखी के पवित्र अवसर पर, हम अपने समाज की शारीरिक और मानसिक भलाई के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं, जो एकता और शक्ति की भावना को प्रतिध्वनित करता है । यह त्योहार उसी का प्रतीक है।

डॉ. साहनी ने इस बात पर जोर दिया कि यह मैराथन केवल एक दौड़ नहीं है, बल्कि यह हमारे युवाओं और समाज को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करने का एक जनांदोलन है। आज के समय में, जब नशीले पदार्थों का सेवन युवाओं के लिए जानलेवा साबित हो रहा है । ऐसे हमें सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। बच्चों को इस बाबाद सजग व शिक्षित करना और समाज को शारीरिक रूप से सशक्त बनाना नशा मुक्त भारत बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है।

प्रतिभागियों के असाधारण प्रयासों को मान्यता देने के लिए, विभिन्न श्रेणियों के तहत कई प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। पुरुष वर्ग के लिए प्रथम पुरस्कार चंद्रपाल चौधरी को दिया गया और महिला वर्ग में भारती ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

डॉ. साहनी ने विजेताओं को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया और फिटनेस और नशे के खिलाफ सामाजिक जागरूकता के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ, वैसाखी सुपरसिख मैराथन सामुदायिक भावना, स्वास्थ्य और बेहतर कल के लिए एक सार्थक पहल के प्रतीक के रूप में विकसित हो रही है।

क्या भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो सकता है ?

जयसिंह रावत

2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत सरकार ने 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री द्वारा इसे एक निर्णायक कदम बताया गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि टीबी आज भी लाखों जिंदगियों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। 347 जिलों में चलाया गया यह अभियान क्या वास्तव में वांछित परिणाम दे पाया? आंकड़े बताते हैं कि टीबी उन्मूलन की राह अब भी कठिन बनी हुई है। क्षय रोग (टीबी) एक संक्रामक बीमारी है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस (Mycobacterium tuberculosis) नामक जीवाणु से फैलती है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है लेकिन शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुँचा सकता है।

भारत में टीबी की स्थिति

भारत में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत टीबी के मामलों में कमी आई है, लेकिन यह गिरावट पर्याप्त नहीं है। 2015 में प्रति 100,000 आबादी पर 237 मामलों की तुलना में 2023 में यह संख्या घटकर 195 हुई, लेकिन यह 100% उन्मूलन से अब भी बहुत दूर है। टीबी से संबंधित मौतों में भी 21.4% की कमी आई है, फिर भी हर साल हजारों लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में टीबी के मामलों में गिरावट की दर वैश्विक औसत (8.3%) से दोगुनी तेज रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दर 2025 तक उन्मूलन के लिए पर्याप्त होगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर टीबी को पूरी तरह खत्म करना है, तो सिर्फ दवाओं से ही नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक सुधारों से भी जुड़कर काम करना होगा।

भारत सरकार ने टीबी के उन्मूलन को गति देने के लिए 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने हरियाणा के पंचकूला में इस पहल की शुरुआत की। यह अभियान 347 जिलों में असुरक्षित आबादी के लिए टीबी की पहचान, निदान में देरी को कम करने और उपचार के परिणामों को बेहतर बनाने पर केंद्रित था लेकिन क्या यह पूरी तरह सफल रहा? विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ 100 दिनों में किसी महामारी जैसी बीमारी को नियंत्रित करना अव्यावहारिक है। टीबी उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयास, मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली, व्यापक जन-जागरूकता, पोषण सुधार और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने की जरूरत है।

टीबी से बचाव और उपचार में कहां चूक हो रही है?

टीकाकरणः बीसीजी (BCG) वैक्सीन नवजात शिशुओं को दी जाती है, लेकिन यह सिर्फ गंभीर टीबी के मामलों से बचाव करती है। सक्रिय टीबी की रोकथाम के लिए नए टीकों की जरूरत है।

जल्दी पहचान और इलाजः टीबी के मामलों की रिपोर्टिंग में अब भी देरी हो रही है, जिससे संक्रमण का प्रसार बढ़ता है।

साफ-सफाई और पोषणः कुपोषण टीबी को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कारक है, लेकिन इस दिशा में सरकार के प्रयास अधूरे हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलः जागरूकता अभियान चल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण और गरीब तबके तक इनकी पहुंच अब भी सीमित है।

क्या भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो सकता है?

भारत ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह लक्ष्य कठिन है। WHO की ₹End TB₹ रणनीति के तहत संक्रमित व्यक्तियों के उपचार पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन मौजूदा गति से यह संभव नहीं दिखता।

टीबी उन्मूलन सिर्फ एक स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है, बल्कि गरीबी, कुपोषण, भीड़भाड़, कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता की कमी से भी जुड़ा हुआ है। अगर सरकार और समाज ने मिलकर अधिक गंभीर प्रयास नहीं किए तो 2025 का लक्ष्य एक असफल वादा बन सकता है।

टीबी के उन्मूलन के लिए सिर्फ संकल्प ही नहीं बल्कि ठोस रणनीति और निरंतर प्रयासों की जरूरत है। 100 दिन का अभियान सराहनीय था, लेकिन यह मात्र एक शुरुआत थी। इसे लंबी अवधि की नीति, सशक्त स्वास्थ्य प्रणाली और सामाजिक सुधारों से जोड़ना होगा। टीबी से मुक्त भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम सभी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और ₹टीबी हारेगा, देश जीतेगा !₹ के संकल्प को पूरी निष्ठा से साकार करेंगे।

हर महिला को कब-कौन सा टेस्ट कराना जरूरी है?

उमेश कुमार साहू

आज की महिला सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की रीढ़ है। वह एक बेटी है, बहन है, माँ है, पत्नी है और सबसे बढ़कर— एक जीवनदायिनी है लेकिन अक्सर दूसरों की देखभाल में वह खुद को नजरअंदाज कर देती है। स्वास्थ्य जैसे अहम विषय पर भी वह तभी ध्यान देती है जब कोई गंभीर दिक्कत सामने आ जाए। यह लेख उसी जिम्मेदारी को याद दिलाने का एक प्रयास है—कि अब वक्त है खुद के लिए जीने का, और सबसे पहले अपना स्वास्थ्य सहेजने का।

स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं, जीवन की पहली ज़रूरत है। ठीक वैसे ही जैसे समय पर शिक्षा, भोजन या आराम जरूरी होता है—वैसे ही हर उम्र की महिला के लिए कुछ खास मेडिकल टेस्ट ज़रूरी होते हैं, जो न केवल संभावित बीमारियों को समय रहते पहचान सकते हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी को लंबा, सुरक्षित और सुखद बना सकते हैं। तो आइए जानें—आपकी उम्र के अनुसार कौन-कौन से टेस्ट जरूरी हैं और उन्हें कब करवाना चाहिए।

1. हड्डियों की जांच (Bone Density Test – DEXA Scan)
कब कराएं: 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र में
क्यों जरूरी: महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद हड्डियों से कैल्शियम तेजी से कम होने लगता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं।
कैसे होता है टेस्ट: DEXA स्कैन द्वारा हड्डियों के घनत्व की जांच की जाती है।

2. ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग (Mammogram)
कब कराएं: 50 से 74 साल की महिलाएं — हर 2 साल में एक बार
क्यों जरूरी: ब्रेस्ट कैंसर प्रारंभिक अवस्था में पकड़ा जाए तो इलाज सफल होता है।
कैसे होता है टेस्ट: स्तनों की एक्स-रे द्वारा गांठ या कैंसर के लक्षणों की जांच होती है।

3. सर्वाइकल कैंसर जांच (Pap Smear / HPV Test)
कब कराएं: 21 से 65 वर्ष की महिलाएं — हर 3 साल में
क्यों जरूरी: यह टेस्ट गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर पूर्व कोशिकाओं की पहचान करता है।
कैसे होता है टेस्ट: Pap Smear में ग्रीवा से कोशिकाएं लेकर जांच की जाती है।

4. कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग (Large Intestine Cancer Test)
कब कराएं: 50 से 75 वर्ष की उम्र में
क्यों जरूरी: यह टेस्ट बड़ी आंत या मलाशय में कैंसर की समय पर पहचान करता है।
टेस्ट विकल्प: कोलोनोस्कोपी, FIT टेस्ट, स्टूल DNA टेस्ट

5. डायबिटीज की जांच (Blood Sugar Test / Fasting Glucose / HbA1c)
कब कराएं: जब ब्लड प्रेशर 135/80 mmHg से अधिक हो या दवा ले रही हों
क्यों जरूरी: डायबिटीज़ आंखों, किडनी, दिल और नसों को प्रभावित कर सकती है।
कैसे होता है टेस्ट: Fasting Blood Sugar और HbA1c टेस्ट द्वारा

6. लिपिड प्रोफाइल (Cholesterol Test)
कब कराएं: 20 वर्ष की उम्र के बाद हर 4-6 साल में
क्यों जरूरी: यह टेस्ट हृदय रोग, स्ट्रोक और ब्लॉकेज के खतरे को दर्शाता है।
टेस्ट में शामिल: Total Cholesterol, LDL, HDL, Triglycerides

7. ब्लड प्रेशर जांच (BP Monitoring)
नॉर्मल BP: 120/80 mmHg — हर 2 साल में
BP 120/80 से 139/89 mmHg: साल में एक बार
क्यों जरूरी: हाई बीपी बिना लक्षण दिए गंभीर नुकसान कर सकता है।

महिला ही समाज की धुरी है। जब वह स्वस्थ रहेगी, तो पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा। स्वास्थ्य की ओर यह छोटा कदम एक लंबी, सुंदर और सशक्त ज़िंदगी की शुरुआत हो सकता है। आज से ही एक डायरी बनाइए, अपनी उम्र के अनुसार जरूरी टेस्ट्स की प्लानिंग कीजिए और जीवन को दीजिए एक नई ऊर्जा।

अंबेडकर जयंती: एक क्रांति का जन्म, एक सपने का सृजन

सपने वही साकार होते हैं, जो हिम्मत और हौसले से बुने जाते हैं। कल्पना करें, एक ऐसे बच्चे की, जिसे स्कूल के दरवाजे पर अपमान का सामना करना पड़े, जिसे पानी की एक घूँट के लिए दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़े। क्या वह बच्चा हार मान लेता है? नहीं! अगर उसका नाम भीमराव रामजी अंबेडकर हो, तो वह न केवल अपने भाग्य को बदल देता है, बल्कि पूरे समाज की नींव को हिला देता है। 14 अप्रैल, डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती, केवल एक तिथि नहीं, बल्कि उस ज्वाला का उत्सव है, जिसने सदियों की गुलामी और भेदभाव की बेड़ियों को तोड़कर भारत को समता, न्याय और मानवता का मार्ग दिखाया। बाबा साहेब, जैसा कि उन्हें प्रेम और सम्मान से बुलाया जाता है, एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार, एक आंदोलन और एक क्रांति थे, जिन्होंने भारत के सामाजिक ताने-बाने को हमेशा के लिए बदल दिया।

1891 में मध्यप्रदेश के महू में एक साधारण परिवार में जन्मे भीमराव का बचपन अभावों, तिरस्कार और सामाजिक बहिष्कार से भरा था। महार जाति से होने के कारण उन्हें उस दौर की क्रूर जातिगत व्यवस्था का शिकार होना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी पीने के लिए उन्हें दूसरों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन इन कठिनाइयों ने उनके इरादों को कमजोर नहीं किया। उनकी असाधारण बुद्धि, ज्ञान की प्यास और शिक्षा के प्रति जुनून ने उन्हें न केवल भारत, बल्कि विश्व के शीर्ष शिक्षण संस्थानों तक पहुँचाया। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों में उन्होंने अर्थशास्त्र, विधि, समाजशास्त्र और राजनीति जैसे विषयों में गहन अध्ययन किया। उनकी विद्वता ऐसी थी कि अंग्रेजी सरकार से लेकर स्वतंत्र भारत तक, हर व्यवस्था उन्हें अपने लिए अपरिहार्य मानती थी।

डॉ. अंबेडकर के लिए शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली हथियार थी। उनका प्रसिद्ध कथन—"शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो"—आज भी वंचित वर्गों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक उत्थान का आधार बनाया और इसके प्रसार के लिए कई संस्थानों की स्थापना की। उनका मानना था कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति शिक्षित और सशक्त नहीं होगा, तब तक समानता और न्याय का सपना अधूरा रहेगा। यही कारण था कि उन्होंने दलितों और वंचितों को शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए अनगिनत प्रयास किए। वे कहते थे कि शिक्षा वह ताकत है, जो मनुष्य को अपनी नियति खुद लिखने की शक्ति देती है।

बाबा साहेब का सामाजिक संघर्ष केवल अधिकारों की माँग तक सीमित नहीं था, यह समाज की चेतना को जागृत करने की ऐतिहासिक लड़ाई थी। 1927 का महाड़ सत्याग्रह इसका जीवंत उदाहरण है, जब उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक जलस्रोतों तक पहुँच की माँग की। यह आंदोलन केवल पानी के अधिकार की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह समाज को यह बताने का प्रयास था

कि हर मनुष्य को बराबरी का हक है। इसके बाद 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन ने एक बार फिर साबित किया कि बाबा साहेब जातिगत भेदभाव को मानवता पर आघात मानते थे। ये आंदोलन केवल प्रतीकात्मक नहीं थे, बल्कि सामाजिक नवजागरण की शुरुआत थे, जिन्होंने लाखों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी सम्मान और समानता के हकदार हैं।

डॉ. अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान का निर्माण है, जिसने स्वतंत्र भारत को एक मजबूत, समतामूलक और न्यायपूर्ण राष्ट्र का आधार प्रदान किया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार किया, जो हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषाई स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और अवसर की समानता की गारंटी देता है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने लाखों लोगों को सामाजिक और आर्थिक मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर दिया। यह व्यवस्था केवल नीति नहीं थी, बल्कि बाबा साहेब का वह वादा था, जो सदियों से उपेक्षित लोगों को सम्मान और अवसर का जीवन देना चाहता था।

बाबा साहेब केवल दलितों के मसीहा नहीं थे, वे महिलाओं के अधिकारों के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक, विवाह की स्वतंत्रता और समान अधिकार देने की कोशिश की गई। यह बिल उस समय के रूढ़िवादी समाज के लिए क्रांतिकारी था, लेकिन तत्कालीन सरकार द्वारा इसे पारित न किए जाने पर उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। यह कदम उनकी उस अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो सिद्धांतों को किसी भी पद या प्रतिष्ठा से ऊपर रखता था।

1956 में बौद्ध धर्म अपनाकर बाबा साहेब ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। यह केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि समानता, करुणा और नैतिकता पर आधारित जीवन दर्शन को अपनाने का संदेश था। नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे ऐसी किसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे, जो मनुष्य को जन्म के आधार पर नीचा समझे। यह कदम सामाजिक चेतना के एक नए युग की शुरुआत था, जिसने लाखों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि धर्म का आधार मनुष्यता और समता होना चाहिए।

डॉ. अंबेडकर का जीवन केवल संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी नहीं है, यह एक प्रेरणा है कि सबसे अंधेरे रास्तों पर भी अगर आत्मविश्वास और विश्वास का दीप जलाया जाए, तो रोशनी जरूर मिलती है। उन्होंने न केवल दलितों और वंचितों को आवाज दी, बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रेरित किया, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके समय में थे। जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और लैंगिक अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई आज भी हमें यह सिखाती है कि बदलाव संभव है, बशर्ते हम हिम्मत और एकजुटता के साथ आगे बढ़ें।

आज, अंबेडकर जयंती पर हमें उनके सपनों का आत्मपरीक्षण करना होगा। क्या हम उस भारत का निर्माण कर पाए हैं, जिसकी कल्पना बाबा साहेब ने की थी? क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ जाति, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो? क्या हम हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान देने में सक्षम हुए हैं? ये सवाल हमें न केवल सोचने के लिए मजबूर करते हैं, बल्कि यह भी याद दिलाते हैं कि बाबा साहेब का सपना अभी पूरी तरह साकार नहीं हुआ है। उनकी जयंती केवल उत्सव का अवसर नहीं है, बल्कि यह संकल्प लेने का दिन है कि हम उनके विचारों को न केवल याद रखेंगे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे।

इस अंबेडकर जयंती पर हम उस अमर ज्योति को प्रज्वलित करें, जो बाबा साहेब ने हमें थमाई थी—समानता की ज्योति, जो हर विभेद को राख कर दे; न्याय की ज्योति, जो हर अत्याचार को ललकारे; और मानवता की ज्योति, जो हर हृदय को करुणा से सराबोर करे। हम संकल्प लें कि एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, जहाँ हर व्यक्ति को उसका हक बिना झिझक मिले, जहाँ हर मन में प्रेम और भाईचारा बसे, और जहाँ हर जीवन सम्मान, समृद्धि और सशक्तिकरण के प्रकाश से दमके। बाबा साहेब का जीवन हमें सिखाता है कि कोई स्वप्न असंभव नहीं, जब उसे हकीकत में बदलने का दृढ़ निश्चय हो। उनकी जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए मार्ग पर अडिग चलें और एक ऐसे समाज को गढ़ें, जो उनकी दूरदर्शी कल्पना का जीवंत प्रतीक बने। जय भीम।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

'गाइडलाइन' से बंधी अब हर शाख़-हर पत्ती [अब 'पर्यावरण' नहीं, 'परमिशन' सर्वोपरि है]

देश में पेड़ लगाना भी अब मंत्रियों की ₹अनुमति₹ से होता है। शायद अब पेड़ों को भी 'वोटर आईडी' और 'आधार लिंकिंग' की ज़रूरत पड़ने वाली है — ताकि सरकार उनकी मौजूदगी को मान्यता दे सके। पौधे भी सोचते होंगे — "काश! हमें भी वोटर लिस्ट में डाल देते, शायद तब हमारी भी कद्र होती।" शासकीय अधिकारी ने बिना मंत्रीजी की इजाजत के पौधे क्या लगा दिए, जैसे भ्रष्टाचार नहीं, हरियाली फैला दी हो।

मंत्रीजी के दौरे से पहले अधिकारी ने सोचा – "कुछ हरियाली हो जाए", लेकिन सिस्टम बोला – "पहले अनुमति, फिर प्रकृति!" बिना ₹गाइडलाइन₹ के पेड़ लगाना अब इतना गंभीर अपराध है, जैसे संविधान की प्रस्तावना में पर्यावरण की जगह 'परमिशनवाद' जोड़ दिया गया हो। माननीयों को छूट है।

अब हाल ये है कि पेड़ लगाने की तारीख भी फाइलों में तय होती है — 20 जून के बाद ही लगाना, वरना पेड़ भी "अवैध निर्माण" घोषित हो सकता है।

नतीजा? अधिकारी निलंबित। अगली बार कोई पेड़ लगाने से पहले मंत्रीजी की आरती उतार ले, फिर कुदाल चलाए। अब 'हरियाली' से पहले 'हुक्मनामा' जरूरी है।

देश बदल रहा है। अब पर्यावरण नहीं, ₹परमिशन₹ हमारी पहली प्राथमिकता है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

डॉ भीमराव अंबेडकर- वैश्विक युवाओं के लिये प्रेरणास्रोत

संजय कुमार सुमन

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था, वह अपने माता-पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे। वह ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबासाहेब के पिता संत कबीर दास के अनुयायी थे और एक शिक्षित व्यक्ति थे।

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर लगभग दो वर्ष के थे जब उनके पिता नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए थे। जब वह केवल छह वर्ष के थे तब उसकी मां का निधन हो गया था। बाबासाहेब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की। अपने स्कूली दिनों में ही उन्हें इस बात से गहरा सदमा लगा कि भारत में अछूत होना क्या होता है। बाबासाहेब अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था किंतु उन्होंने जीवन में आयी सभी चुनौतियों का डट कर सामना किया व दुनिया में अपनी एक विशिष्ठ पहचान बनाई।

डॉ. अंबेडकर अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में ही कर रहे थे। दुर्भाग्यवश, डॉ अंबेडकर की मां की मौत हो गई। उनकी चाची ने उनकी देखभाल की। बाद में, वह मुंबई चले गए। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान, वह अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित हुए। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास होने के बाद उनकी शादी एक बाजार के खुले छप्पड़ के नीचे हुई।

भीमराव का प्राथमिक शिक्षण दापोली और सतारा में हुआ। बंबई के एलफिन्स्टोन स्कूल से वह 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उसमें भेंट स्वरुप उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने स्वलिखित पुस्तक 'बुद्ध चरित्र' उन्हें प्रदान की। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड की फेलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढने पर मनाही होने से वह फारसी लेकर उत्तीर्ण हुये। बी.ए. के बाद एम.ए. के अध्ययन हेतु बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की पुन: फेलोशिप पाकर वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुये। सन 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा पास की। इस हेतु उन्होंने अपना शोध 'प्रायीन भारत का वाणिज्य' लिखा था। उसके बाद 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की, उनके पीएच.डी. शोध का विषय था 'ब्रिटिश भारत में प्रातीय वित का विकेन्द्रीकरण'।

फेलोशिप समाप्त होने पर उन्हें भारत लौटना था अत: वे ब्रिटेन होते हुये लौट रहे थे। उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स एण्ड पोलिटिकल सांइस में एल.एससी. और डी. एस सी. और विधि संस्थान में बार-एट-लॉ की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया और भारत लौटे। सब से पहले छात्रवृति की शर्त के अनुसार बडौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। पूरे शहर में उनको किराये पर रखने को कोई तैयार नही होने की गंभीर समस्या से वह कुछ समय के बाद ही मुंबई वापस आये। वहां परेल में डबक चाल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढाई को पूरी करने हेतु पार्ट टाईम अध्यापकी और वकालत कर अपनी धर्मपत्नी रमाबाई के साथ जीवन निर्वाह किया। सन 1919 में डॉ. अम्बेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथबरो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी। उन होंने मूक और अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरुक बनाने के लिये मूकनायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकायें संपादित कीं और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिये वह लंदन और जर्मनी जाकर वहां से एम. एस सी., डी. एस सी., और बैरिस्टर की उपाधियाँ प्राप्त की। उनके एम. एस सी. का शोध विषय साम्राज्यीय वित के प्रातीय विकेन्द्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन और उनके डी.एससी उपाधि का विषय रुपये की समस्या उसका उद्भव और उपाय और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास था।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एल.एलडी और

उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डी. लिट्. की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर वैश्विक युवाओं के लिये प्रेरणा बन गये क्योंकि उनके नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डी.लिट्. आदि कुल १६ उपाधियां जुडी है।

डॉ. अम्बेडकर ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और स्वतंत्रता के बाद इसके सुधारों में भी अपना योगदान दिया। इसके अलावा बाबासाहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन को बाबासाहेब द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर किया गया था।

डॉ. अंबेडकर का प्रकाशवान जीवन दर्शाता है कि वह विद्वान और कर्मशील व्यक्ति थे। सबसे पहले, उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अर्थशास्त्रि राजनीति, कानून, दर्शन और समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया जहां पर उन्हें कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने और पुस्तकालयों में नहीं बिताया। उन्होंने आकर्षक वेतन के साथ उच्च पदों को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह दलित वर्ग के अपने भाइयों को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपना जीवन समानता, भाईचारे और मानवता के लिए समर्पित किया। उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए पुरजोर कोशिश की।

डॉ. भीमराव के जीवन के इतिहास से गुजरने के बाद, उनके मुख्य योगदान और उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन और विश्लेषण करना बहुत आवश्यक और उचित है। एक विचार के अनुसार तीन बिंदु है जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज कई आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा है। डॉ. अंबेडकर के विचार और कार्य इन समस्याओं का समाधान करने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते है। डॉ भीमराव अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच-नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफी अपमान का सामना किया। डॉ भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में यह साफ-साफ कहा था कि "जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा, वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा।" वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया।

डॉ भीमराव अंबेडकर सन 1948 से मधुमेह (डायबिटीज) से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार रहे थे। 3 दिसंबर 1956 को डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म उनके को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली थी। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया। इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है।

अमेरिका ईरान के बीच मस्कट में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर वार्ता संपन्न -19 अप्रैल 2025 को फिर बैठक

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर चल रही अशांति, युद्ध,बम गोला बारूद के बीच रूस-यूक्रेन इजरायल-गाजा में युद्ध व लेबनान सीरिया व यमन में अशांति के बीच एक सकारात्मक पहलू हुआ कि ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर वार्ता हुई, जिसे ईरान ने अप्रत्यक्ष वार्ता बताया तोअमेरिका ने प्रत्यक्ष बताया जिसकी चर्चा हम नीचे पैराग्राफ में करेंगे। लंबे समय से दुश्मन रहे ईरान और अमेरिका शनिवार (12 अप्रैल, 2025) को मस्कट में संभावित परमाणु समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से वार्ता किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार (7 अप्रैल, 2025) को चौंकाने वाली घोषणा की थी। परंतु मेरा मानना है कि दुनियाँ के हर देश को वैश्विक शांति के लिए ज़रूरत के अनुसार चार कदम पीछे हटना चाहिए व पावर दिखाने वाले देशों को भी नम्र होकर शांति समझौते करना समय की मांग है।चूँकि अमेरिका ईरान के बीच मस्कट में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर वार्ता हुई,जो 19 अप्रैल 2025 को फिर बैठने का निर्णय लिया गया है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने,कूटनीति को सद्भावना, सहयोग, मुद्दे सुलझाने के संकल्प कर सकारात्मक नतीजे के अंजाम तक लाना जरूरी है। बता दें यह पूरी जानकारी मीडिया में अपडेट्स के सहयोग से उठाई गई है।

साथियों बात अगर हम मस्कट में 12 अप्रैल 2025 को हुई वार्ता की करें तो,ईरान और अमेरिका के दूतों ने शनिवार को ओमान में तेहरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू की। हालांकि तत्काल कोई समझौता होने की संभावना नहीं थी,लेकिन दोनों देशों के बीच आधी सदी से चली आ रही दुश्मनी के कारण बातचीत में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। हाल के दिनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अगर वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ आम सहमति बनाने में विफल रहता है तो वह ईरान को ऐसा करने से रोकेगा।राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए तेहरान पर हमला करने की धमकी दी है, यदि समझौता नहीं हुआ,इसपर ईरान ने चेतावनी दी है कि वह हथियार स्तर के करीब संवर्धित अपने यूरेनियम भंडार के साथ परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है। ईरान ने वार्ता को 'अप्रत्यक्ष' बताया,ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा,ये वार्ता ओमानी मेजबान द्वारा नियोजित स्थान पर होगी, जिसमें इस्लामी गणराज्य ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि हॉल और किनारों में बैठेंगे, तथा ओमानी विदेश मंत्री के माध्यम से एक-दूसरे को अपने विचार और स्थिति से अवगत कराएंगे, जबकि ट्रंप और विटकॉफ दोनों ने वार्ता को प्रत्यक्ष बताया है, ईरानी पक्ष इसे अप्रत्यक्ष वार्ता कहता है।लेकिन दोनों दलों के बीच सीधी वार्ता नहीं हो रही है।दोनों दल अलग-अलग कमरों में बैठे हैं और वे ओमान के विदेश मंत्री के जरिये वार्ता कर रहे हैं। यह जानकारी ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक्स पर दी है।

साथियों बात अगर हम ईरान अमेरिका वार्ता के बैकग्राउंड की करें तो,अमेरिका-ईरान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। इस बीच ईरान की शनिवार को अमेरिका के साथ ओमान में बातचीत हुई है। ओमान में हुई इसी बैठक को लेकर ईरान ने बड़ा बयान दिया था। विदेश मंत्री ने कहा था कि ईरान ईमानदारी से न्यूक्लियर डील को अंतिम रूप देने के इरादे से बातचीत में शामिल होने को तैयार है, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ किया कि ये वार्ता सीधी नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष होगी, और अमेरिका को पहले ये मानना होगा कि सैन्य विकल्प कोई विकल्प नहीं है,हाल ही में अमेरिका केराष्ट्रपति ने ईरान को न्यूक्लियर डील पर बातचीत कहने को कहा था और साथ ही धमकी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान को बमबारी का सामना करना पड़ेगा।ट्रंप की चेतावनी थी, बात नहीं बनी तो भुगतना होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को व्हाइट हाउस में इजराइली प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान वार्ता का खुलासा करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर बातचीत नाकाम रही, तो ईरान के लिए ये बहुत बुरा दिन होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक लेख में लिखा है कि हमारा देश गर्वित है, और दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकेगा, उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर ईमानदार है, तो उसे साबित करना होगा कि वह डील को निभाएगा, ईरान कभी भी परमाणु हथियारों की दिशा में नहीं बढ़ा, लेकिन हम अपनी मंशा को लेकर स्पष्टीकरण देने को तैयार हैं।

साथियों बात अगर हम ईरान अमेरिका तनाव में इजरायल की एंट्री की करें तो, ईरान अमेरिका के बीच चल रही

तनातनी में अब ईजराइल ने भी एंट्री मार ली है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह ईरान के लिए लीबिया जैसा मॉडल चाहते हैं, जहां अमेरिका खुद जाकर परमाणु स्थलों को खत्म करे, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका के साथ ईरान की बात नहीं बनी, तो सैन्य कार्रवाई तय है। ईरान की दो टूक न डील खत्म करेंगे, न झुकेंगे ईरानी अधिकारियों ने बीबीसी को बताया कि वे अपने परमाणु कार्यक्रम को कभी नहीं खत्म करेंगे और लीबिया मॉडल किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि उनका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। 2015 की डील से बाहर निकलने के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तल्खी बढ़ती गई है। जो अभी 19 अप्रैल को देखना होगा।

साथियों बात अगर हम देर रात मीडिया में आई जानकारी के अनुसार वार्ता के नतीजे की करें तो, अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच हुई पहली सीधी वार्ता में इस मुद्दे पर 19 अप्रैल को और चर्चा करने पर सहमति बनी है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह जानकारी दी। ईरान के सरकारी टेलीविजन की खबर के मुताबिक, वार्ता के अंत में अमेरिका के पश्चिम एशिया में दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ओमान के विदेश मंत्री की उपस्थिति में संक्षिप्त बातचीत की। इससे दशकों से तनावपूर्ण संबंध वाले दोनों देशों के बीच सीधी वार्ता होने का संकेत मिलता है। मीडिया के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान की ओर से आ रही खबरों की तत्काल पुष्टि नहीं की है। खबरों के मुताबिक, दोनों पक्षों ने ओमान के बाहरी इलाके में एक स्थान पर दो घंटे से अधिक समय तक बातचीत की, दोनों देशों के बीच करीब 50 साल से जारी दुश्मनी के बीच बातचीत का महत्व और भी बढ़ गया है। बता दें बघेई ने कहा था,हम कूटनीति को एक वास्तविक और ईमानदार अवसर दे रहे हैं, ताकि बातचीत के माध्यम से हम एक ओर परमाणु मुद्दे पर आगे बढ़ सकें, और दूसरी ओर हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिबंधों को हटाया जाए। बघेई ने कहा था, देखिए, यह तो बस एक शुरुआत है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इस चरण में दोनों पक्ष ओमानी मध्यस्थ के माध्यम से अपनी मौलिक स्थिति प्रस्तुत करेंगे।इसलिए,हमें उम्मीद नहीं है कि वार्ता का यह दौर लंबा चलेगा।' इससे पहले अराघची ने ईरानी पत्रकारों से बात की थी। एक आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना द्वारा जारी एक ऑडियो क्लिप में अराघची ने कहा,अगर दोनों पक्षों में पर्याप्त इच्छाशक्ति है, तो हम कार्यक्रम तय करेंगे। लेकिन इस बारे में बात करना अभी भी जल्दबाजी होगी।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विशिष्ट ना करें तो हम पाएंगे कि अमेरिका ईरान के बीच मस्कट में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर वार्ता संपन्न -19 अप्रैल 2025 को फ़िरे बैठक।वार्ता को लेकर ईरान अमेरिका के अलग-अलग दावे- ईरान ने अप्रत्यक्ष वार्ता बताया तो अमेरिका ने प्रत्यक्ष बताया।अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने, कूटनीति को सद्भावना, सहयोग व मुद्दे सुलझाने का संकल्प कर,सकारात्मक नतीजों के अंजाम तक लाना ज़रूरी।

सपा,बसपा व कांग्रेस छोड़ सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने रालोद का थामा दामन

परिवहन विशेष न्यूज

मथुरा। में कांग्रेस, बसपा और सपा के कार्यकर्ताओं ने रालोद की सदस्यता ग्रहण की।

विधायक विधान परिषद योगेश नौहवार जी के प्रयास से सपा बसपा एवं कांग्रेस के सैकड़ो कार्यकर्ता ने अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़कर रालोद की सदस्यता ग्रहण की।

इस मौके पर राष्ट्रीय लोक दल पार्टी में शामिल हुए लोगों ने कहा कि रालोद ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल रही है। रालोद सभी वर्गों की सच्ची हितेषी है। इसीलिए उन्होंने रालोद का दामन थामा है। वह पार्टी की नीति एवं कार्यक्रम में पूर्ण विश्वास रखते हैं और पार्टी के आगे बढ़ाने के लिए निष्ठा के साथ कार्य करते रहेंगे। रालोद के विधायक योगेश नौहवार जी ने कहा कि पार्टी की नीति कार्यक्रमों से प्रभावित होकर रालोद की तरफ सभी वर्गों के लोग अब साथ आ रहे हैं। पार्टी का दिन प्रतिदिन जनाधार बढ़ रहा है। पार्टी सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। कार्यक्रम में सलीम ख़ान सद्दाम ख़ान, अफ़ज़ल ख़ान (नौहझील) अकबर ख़ान विधौनी, कल्लू ख़ान पालखेड़ा, लुकमान ख़ान, मुर्रा ख़ान जंघावली, मंशूर ख़ान, शाहिद तौहीद कुरैशी, रफ़ीक़, सलमान, अतीक, शाहरुख़, राजा, साहिल, आदिल, अकील, साहिल शाह,जाकिर, नाजिम, फ़हीम, समीर, पपुआ, अनीस, चाँद आदि सैंकड़ों लोगों को विधायक योगेश नौहवार ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कराई।

इसी दौरान विधान परिषद विधायक योगेश नौहवार ने हर्ष के साथ खुशी जाहिर करते हुए रालोद में शामिल होने वाले सभी कार्यकर्ताओं का रालोद परिवार में स्वागत किया।

टाटा कर्व के डीज़ल बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की अग्रिम भुगतान के बाद जाएगी कितनी ईएमआई

परिवहन विशेष न्यूज

कार फाइनेंस योजना टाटा मोटर्स की ओर से कूप एसयूवी सेगमेंट में Tata Curvv को ऑफर किया जाता है। इसके Diesel में बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर बजट घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माता Tata Motors की ओर से भारतीय बाजार में कूप एसयूवी सेगमेंट में Tata Curvv को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। कंपनी की ओर से डीजल में ऑफर किए जाने वाले बेस वेरिएंट को अगर खरीदकर घर लाना चाहते हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Tata Curvv Smart Diesel Price

Tata की ओर से Curvv के डीजल में बेस वेरिएंट के तौर पर Smart को ऑफर किया जाता है। कंपनी इस कूप एसयूवी के बेस वेरिएंट को 11.50 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रही है। अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो 11.50 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 1.12 लाख रुपये का रजिस्ट्रेशन टैक्स, करीब 51 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा टीसीएस चार्ज के तौर पर 11499 रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 13.30 लाख रुपये हो जाती है।

दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

अगर Tata Curvv डीजल के बेस वेरिएंट Smart को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 11.30 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 11.30 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 18188 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Car

अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 11.30 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 18188 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Tata Curvv डीजल के बेस वेरिएंट Smart के लिए करीब 3.97 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 17.27 लाख रुपये हो जाएगी।

किनसे होता है मुकाबला

Tata Motors की ओर से Curvv को कूप एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Citroen Basalt, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Hyundai Creta, Honda Elevate जैसी एसयूवी के साथ होता है।

कैसा है सुजुकी का नया स्कूटर, खरीदने में होगी समझदारी या दूसरे विकल्प हैं बेहतर

परिवहन विशेष न्यूज

सुजुकी की ओर से 125 सीसी सेगमेंट में 2025 Suzuki Access 125 को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। पुराने के मुकाबले नए वर्जन में क्या बदला गया है। इंजन माइलेज फीचर्स राइड हैंडलिंग के साथ ही इसे चलाने का अनुभव कैसा रहा। चलाने के दौरान हमने इसे किन किन कसौटियों पर परखने की कोशिश की। क्या यह हमारे टेस्ट में पास हुआ या नहीं। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख दो पहिया निर्माताओं में शामिल सुजुकी की ओर से 125 सीसी में एक्सेस स्कूटर को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इस स्कूटर के अपडेटिड वर्जन को जनवरी 2025 में ऑटो एक्सपो के दौरान पेश किया गया था। कई बदलावों के साथ इसे ऑफर किया गया है, जिसे हमने हाल में ही चलाकर देखा और कई कसौटियों पर परखकर देखा। फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के मामले में क्या यह स्कूटर आपके लिए फायदे का सौदा बन सकता है या फिर दूसरे विकल्प को चुनना बेहतर होगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लुक्स में हुए हल्के बदलाव

सुजुकी की ओर से 125 सीसी सेगमेंट में अपने स्कूटर एक्सेस को ऑफर किया जाता है। देखने में तो स्कूटर पुराने वर्जन की तरह ही लगता है लेकिन इसमें कुछ हल्के बदलाव किए गए हैं, जिससे थोड़ा नयापन महसूस होता है। स्कूटर के फ्रंट में एलईडी हेडलाइट्स दी गई है। हेडलाइट के ऊपर क्रोम का उपयोग भी किया गया है। इसमें एक छोटी डीआरएल दी भी गई है। इसके अलावा फ्रंट में दिए गए इंडीकेटर हेलोजन ही

मिलते हैं। कुल मिलाकर अगर पुराने और नए एक्सेस स्कूटर के लुक्स की बात करें तो आपको इसमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। स्कूटर में आपको हैजार्ड लाइट्स के लिए अलग से बटन दिया गया है, जो रात के समय सड़क पर खड़े रहने के दौरान आपके काम आ सकता है। इसके अलावा रात के समय हेडलाइट की रोशनी भी ठीक है।

कैसा है डायमेंशन

सुजुकी एक्सेस स्कूटर का व्हीलबेस 1260 एमएम का है। 680 से 690 एमएम की चौड़ाई और 1155 एमएम की ऊंचाई और 160 एमएम की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। अच्छी बात यह है कि स्कूटर की सीट की लंबाई-चौड़ाई थोड़ी बेहतर हुई है जिससे दो लोग आसानी से स्कूटर पर बैठकर कुछ सामान को बीच में भी रख सकते हैं। फ्रंट में बड़ा फ्लोर बोर्ड दिया गया है, जिससे ज्यादा हाइट वाले भी बिना परेशानी स्कूटर को चला पाएंगे। स्कूटर में 5.3 लीटर के पेट्रोल टैंक को बूट स्पेस के साथ दिया गया है जिसके कारण करीब 24.4 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जिसमें आप सिर्फ एक फुल साइज हेलमेट ही रख पाएंगे। पेट्रोल भरवाने के लिए आपको चाबी से ही एक्सेस दिया गया है।

कैसे हैं फीचर्स

सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर में 12 इंच के टायर और फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है। रियर में 10 इंच का ही टायर मिलता है और दोनों पहियों में अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। हेडलाइट के साथ ही रियर व्यू मिरर्स में भी क्रोम का उपयोग किया गया है। साइड प्रोफाइल में भी एग्जॉस्ट पर क्रोम का उपयोग किया गया है। स्कूटर में डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है जिसमें ट्रिप मीटर भी मिलता है। इसके साथ री-सेट के बटन की क्वालिटी भी अच्छी है। इस मीटर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है और इसके फ्रंट में दो बोतल होल्डर मिलते हैं, जिसके साथ ही यूएसबी पोर्ट भी मिलता है। सफर के दौरान आप आसानी से अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं। छोटा-मोटा सामान रखने के लिए भी इसके फ्रंट में दो हुक मिलते हैं।

कितना दमदार इंजन

सुजुकी की ओर से एक्सेस 125 में 124 सीसी के इंजन से 6.2 किलोवाट की पावर और 10.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। स्कूटर में सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ ही फ्यूल इंजेक्टिड तकनीक को दिया गया है। इस स्कूटर को हमने पुरानी दिल्ली की भीड़ वाली सड़कों के साथ ही साउथ दिल्ली और नोएडा की खुली सड़कों पर भी चलाया। इस दौरान हमने इस स्कूटर से करीब 55 से 60 किलोमीटर के आस-पास की माइलेज ली।

हैंडलिंग और ब्रेकिंग

हमने कुछ दिनों तक स्कूटर को अलग अलग सड़कों और कंडीशन में चलाकर देखा और इस दौरान हमने करीब 400 किलोमीटर तक चलाया। चलाते हुए हमने इसे मोड़ते हुए काफी टर्न करने की कोशिश की, साथ ही तेज चलाने और कम स्पीड में भी चलाकर देखा। समय मिलने पर अचानक से ब्रेक भी लगाकर देखे और अचानक से पूरा एक्सेलेरेशन भी करके देखा। इस दौरान यह समझ आया कि तेज स्पीड पर अगर अचानक से ब्रेक लगाए जाते हैं तो यह काफी आसानी से तो रुकता ही है साथ ही पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है।

समीक्षा

सुजुकी की ओर से 2025 में लॉन्च किए गए नए Suzuki Access 125 को हमने कुछ दिनों तक चलाया। पहले के मुकाबले नए वर्जन में जो बदलाव किए गए हैं उससे यह एक बेहतर विकल्प बन जाता है। अपने सेगमेंट में अन्य स्कूटर्स के मुकाबले यह ज्यादा पावर के इंजन के साथ आता है। कर्ब वेट के मामले में यह Yamaha Fascino से पीछे रहता है लेकिन बाकी स्कूटर्स से आगे निकल जाता है। बूट स्पेस में भी सिर्फ TVS Jupiter से ही पीछे रह जाता है। जबकि डेस्टिनी और फैसिनो इस मामले में एक्सेस से पीछे रह जाते हैं। पुराने के मुकाबले नए एक्सेस का टॉर्क थोड़ा बेहतर हुआ है। साथ ही इसकी इसकी माइलेज भी बेहतर हुई है। ऐसे में 82900 रुपये से लेकर 94500 रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर अगर 125 सीसी सेगमेंट में इस स्कूटर को खरीदा जाता है तो यह आपको इंजन, परफॉर्मेंस, माइलेज के मामले में निराश नहीं करेगा।

सड़क निर्माण में केंद्र सरकार करेगी 10 लाख करोड़ का निवेश, पूर्वोत्तर में अमेरिका जैसी होंगी हाईवे

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत की सड़क नेटवर्क को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार आने वाले दो वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश करने की योजना बना रही है। इसका सबसे बड़ा फोकस पूर्वोत्तर भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों में होगा, जहां की सड़कें जल्द ही अमेरिकी सड़कों की तरह नजर आएंगी।

गडकरी ने कहा कि कठिन भूगोल और सीमाओं से सटे इलाकों को देखते हुए पूर्वोत्तर में बेहतरीन सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'हमारा प्रयास है कि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संरचनाओं की बराबरी पर लाया जाए।'

पूर्वी भारत में 784 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू

गडकरी के मुताबिक पूर्वी राज्यों में 21,355 किलोमीटर लंबे 784 सड़क परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिन पर कुल मिलाकर करीब 3.73 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन परियोजनाओं में सड़क परिवहन मंत्रालय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) की बड़ी भूमिका होगी।

राज्यवार निवेश की स्थिति

असम: 57,696 करोड़ रुपये

बिहार: 90,000 करोड़ रुपये

झारखंड: 53,000 करोड़ रुपये

पश्चिम बंगाल: 42,000 करोड़ रुपये

ओडिशा: 58,000 करोड़ रुपये

पूर्वोत्तर (असम को छोड़कर): 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक

नागपुर में चल रहा पायलट प्रोजेक्ट

गडकरी ने बताया कि नागपुर में 170 करोड़ रुपये की लागत से एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। इसमें 135 सीटर बस शामिल है, जो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा से चलेगी और बेहद किफायती होगी। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो इसे दिल्ली-जयपुर जैसे व्यस्त रूट्स पर भी लागू किया जाएगा।

गडकरी ने बताया कि देश का नेशनल हाईवे नेटवर्क 2014 में 91,287 किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 1,46,204 किलोमीटर हो गया है। इसके अलावा, दो लेन से कम हाईवे की संख्या अब 30% से घटकर सिर्फ 9% रह गई है।

2024–25 में NHAI ने 5,150 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 5,614 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

बैटरी, रेंज, फीचर्स और कीमत में किस इलेक्ट्रिक गाड़ी को खरीदना होगा समझदारी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कम बजट वाली इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए कई कंपनियों की ओर से बेहतरीन फीचर्स वाली कारों को लाया जा रहा है। JSW MG की ओर से Windsor EV को ऑफर किया जाता है। जिसका सीधा मुकाबला Tata Curvv EV के साथ होता है। MG Windsor EV और Tata Curvv EV के बीच बैटरी, रेंज, फीचर्स और कीमत में किसे खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्प (MG Windsor EV Vs Tata Curvv EV) साबित हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

MG Windsor EV Vs Tata Curvv EV Features

MG Windsor EV में एलईडी प्रोजेक्टर हैडलैंप, एलईडी डीआरएल, 17 और 18 इंच के टायर, फ्लश डोर हैंडल, ग्लास एंटीना, क्रोम फिनिश विंडो बेल्टलाइन, नाइट ब्लैक इंटीरियर के साथ गोल्डन टच हाईलाइट्स, लैदर पैक के साथ डैशबोर्ड, ड्राइवर आर्मरेस्ट, डोर ट्रिम, स्टेयरिंग व्हील दिया गया है। एंबिएंट लाइट्स, रियर एसी वेंट्स, पीएम 2.5 फिल्टर, 10.1 इंच टच डिस्प्ले, सात और 8.8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 15.6 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, यूएसबी चार्जर पोर्ट, वायरलैस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, 6 स्पीकर और 9 स्पीकर इनफिनिटी ऑडियो सिस्टम का विकल्प, पैनोरमिक सनरूफ, एयरो लाउंज सीट्स, वेंटिलेटिड सीट्स, 6वे पावर एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट, स्मार्ट एंट्री सिस्टम, स्मार्ट स्टार्ट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक टेंपरेचर कंट्रोल, वायरलैस स्मार्टफोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं।

वहीं Tata Curvv EV में शॉर्क फिन एंटीना, बॉडी कलर्ड बंपर, एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलाइट, पैनोरमिक सनरूफ, 17 इंच अलॉय व्हील्स, पियानो ब्लैक इंटीरियर, 26.03 सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एयर प्यूरीफायर, ऑटो हेडलैंप, क्रूज कंट्रोल, फॉलो मी हेडलैंप, पावर विंडो, रेन सेंसिंग वाइपर, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं।

MG Windsor EV Vs Tata Curvv EV Battery and Range

MG Windsor EV में कंपनी की ओर से 38 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया गया है। जिसे 0-100 फीसदी चार्ज करने में 13.8 घंटे का समय लगता है। फास्ट चार्जर के जरिए इसे 55 मिनट में 0-80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। विंडसर ईवी में परमानेंट सिंकोरियस मोटर दी गई है जिससे 136 पीएस की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जिससे इसे 331 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

वहीं Tata Curvv EV में 45 kWh और 55 kWh क्षमता की दो बैटरी के विकल्प मिलते हैं। जिसे 0-100 फीसदी चार्ज करने में घंटे का समय लगता है। कर्व में लगी मोटर से इसे 110 किलोवाट की पावर और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जिससे इसे 0-100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने में 8.6 सेकेंड लगते हैं। सिंगल चार्ज में इसको 502 किलोमीटर की रेंज मिलती है।

MG Windsor EV Vs Tata Curvv EV Price

MG Windsor EV को 13.99 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत से ऑफर किया जाता है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपये रखी गई है।

वहीं Tata Curvv EV की एक्स शोरूम कीमत 17.49 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 21.99 लाख रुपये है।

कल लॉन्च होगी वोक्सवैगन टिगुआन आर लाइन एसयूवी, मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन, जानें कितनी हो सकती है कीमत

परिवहन विशेष न्यूज

टिगुआन आर लाइन एसयूवी भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। जर्मनी की वाहन निर्माता Volkswagen की ओर से कल औपचारिक तौर पर फुल साइज एसयूवी के तौर पर Tiguan R Line SUV को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें किस तरह के फीचर्स मिलेंगे। कितना दमदार इंजन मिलेगा। किस कीमत पर इसे लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जिसे देखते हुए निर्माताओं की ओर से भी कई साइज में एसयूवी की बिक्री की जाती है। फॉक्सवैगन की ओर से भी कल भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर Volkswagen Tiguan R Line SUV को लॉन्च कर दिया जाएगा। इस एसयूवी में किस तरह के फीचर्स को दिया जाएगा। कितना दमदार इंजन इसमें मिलेगा। किस कीमत पर इसे लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्च होगी Volkswagen Tiguan R Line SUV

भारत में औपचारिक तौर पर कल तिगुआन आर-लाइन एसयूवी को लॉन्च कर दिया जाएगा। फॉक्सवैगन की ओर से इस एसयूवी को फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में लाया जाएगा। इसके लिए पहले ही बुकिंग को शुरू कर दिया गया है।

कितना दमदार इंजन

Volkswagen Tiguan R Line में दो लीटर की क्षमता का टीएसआई ईवो इंजन दिया जाएगा। इस इंजन से एसयूवी को 204 पीएस की पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इसमें 7स्पीड डीएसजी ट्रांसमिशन को दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें 4मोशन ऑल व्हील ड्राइव क्षमता को दिया जाएगा, जिससे इसे किसी भी तरह की सड़क पर चलाया जा सकता है।

कैसे होंगे फीचर्स

Volkswagen Tiguan R Line में निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाएगा। लॉन्च से पहले एसयूवी के कई और फीचर्स की जानकारी को सार्वजनिक किया गया है। इसमें 15 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन को दिया जाएगा। इसके साथ ही वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आईडीए वॉयस असिस्टेंट, रोटरी कंट्रोलर के साथ स्क्रीन, आठ स्पीकर ऑडियो सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले जैसे कई फीचर्स को दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें मल्टी जोन

क्लाइमेट कंट्रोल, दो वायरलेस चार्जिंग पॉड, एंबिएंट लाइट, पैनोरमिक सनरूफ, मैट्रिक्स हेडलाइट, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट, एलईडी डीआरएल, रूफ रेल जैसे फीचर्स को भी दिया जाएगा। एसयूवी में सेफ्टी के लिए नौ एयरबैग, टीपीएमएस, हिल स्टार्ट असिस्ट और हिल डीसेंट कंट्रोल, फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक, 21 फीचर्स के साथ Level 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स को दिया जाएगा।

कितनी होगी कीमत

फॉक्सवैगन तिगुआन आर लाइन की सही कीमत की जानकारी मिल पाएगी। लेकिन इसकी संभावित एक्स शोरूम कीमत 40 लाख रुपये के आस-पास हो सकती है। खास बात यह है कि इस एसयूवी को सीबीयू के तौर पर भारत में ऑफर किया जाएगा।

किनसे है मुकाबला

फॉक्सवैगन की ओर से तिगुआन आर-लाइन को फुल साइज एसयूवी के तौर पर लाया जाएगा। इस सेगमेंट में इस एसयूवी का सीधा मुकाबला Toyota Fortuner Legender, MG Gloster के साथ होगा। इसके अलावा इसे जल्द ही लॉन्च होने वाली नई Skoda Kodiaq और MG Majestor से भी चुनौती मिलेगी।

कार में करवा लें ये ट्रीटमेंट, स्क्रैच लगने का टेंशन हो जाएगा खत्म

परिवहन विशेष न्यूज

हम यहां पर आपको ऐसे कोटिंग के बारे में बता रहे हैं। इसे करवाने के बाद आपको कार के पेंट को सड़क के मलबे पत्थरों और अन्य वस्तुओं से होने वाले नुकसान से बचाने का काम करता है। सूरज की रोशनी से कार के पेंट के फीका पड़ने का खतरा बहुत कम हो जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

नई दिल्ली। हर किसी को अपनी कार से बहुत प्यार होता है। अगर उनकी कार में थोड़ा सा भी स्क्रैच लग जाए, तो उन्हें बहुत दुख होता है। इतना ही कार में स्क्रैच लगने की वजह से कुछ वर्षों में काफी ज्यादा पुरानी लगने लग जाती है। जिसे देखते हुए हम आपको यहां पर आपको आफ्टरमार्केट में चल रहे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं। इसे अपनी कार पर करवाने के बाद आपको उसपर लगने वाले स्क्रैच की टेंशन तकरीबन खत्म हो जाएगा। वहीं, अगर आप इसे नई कार पर करवा लें, तो आपको गाड़ी की पूरी लाइफटाइम तक उसे कलर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए इसके बारे में जानते हैं और इसे करवाने में आपका कितना खर्च आएगा।

कार पर लगवाना होगा ये फिल्म

जिस तरह से आप अपने फोन को स्क्रैच या टूटने से बचाने के लिए टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से कारों को इनसे सुरक्षित रखने के लिए पेंट प्रोटेक्शन फिल्म फी जरूरत होती है, जिसे PPF भी कहा जाता है। कारों में PPF लगवाना काफी ट्रेंड में चल रहा है। इसे कार पर लगावाने से वह सुरक्षित रहने के साथ ही हमेशा नई जैसी दिखाई देती है।

क्या है PPF ?

PPF कोटिंग में कार के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट लगाई जाती है, जो उनके पेंट को सेफ रखने का काम करती है। अगर आप अपनी कार में एक बार PPF करवा लेते हैं, तो आपकी गाड़ी से लाइफटाइम तक ओरिजिनल कलर निकलने की टेंशन खत्म हो जाती है। इसके साथ ही आपकी कार पर लगने वाला टेंशन भी दूर हो जाता है। इतना ही नहीं अगर आप कार को शैम्पू से अच्छे से धुलवा देते हैं, तो आपकी कार देखने में एकदम नई जैसी लगने लगती है। यह आपकी कार के पेंट को सड़क के मलबे, पत्थरों और अन्य वस्तुओं से होने वाले नुकसान से बचाने का काम करता है। सूरज की रोशन से कार के पेंट के फीका पड़ने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसका पेंट सेफ रहने से जब आप अपनी कार को बेचेंगे, तो वह नई जैसी लगेगी, जिसकी वजह से आपको उसकी ज्यादा कीमत भी मिल सकती है।

PPF कोटिंग का कितना खर्चा ?

अगर आप अपनी कार के ऊपर PPF कोटिंग करवाते हैं, तो इसकी कीमत 30 हजार रुपये से शुरू होती है। जिन लोगों को अपनी कार को हमेशा नई जैसा रखना चाहते हैं, उन लिए यह बेस्ट है।

अंतरिक्ष प्रवास तेज करता है बुढ़ापे की प्रक्रिया

विजय गर्ग

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर विवशतावश नौ महीने बिताने के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स सकुशल लौट आए लेकिन धरती पर लौटने पर जब वे अपने क्रू ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकले तो उन्हें व्हीलचेयर पर रखा गया। दोनों अंतरिक्ष यात्री बहुत अच्छी सेहत में नहीं दिखे। आईएसएस पर शून्य-गुरुत्वाकर्षण के वातावरण में रह कर उनकी मांसपेशियां कमजोर हो गईं और उनकी हड्डियों का घनत्व भी कम हो गया जिससे उनके लिए चलना या खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। अंतरिक्ष यात्रियों की जोड़ी दुबली-पतली भी दिखाई दी। कुछ पर्यवेक्षकों ने पाया कि पिछले जून में अंतरिक्ष यात्रा पर निकलने के बाद से वे काफी बूढ़े हो गए हैं।

वैसे नौ महीने का प्रवास अंतरिक्ष में बिताया गया सबसे लंबा समय नहीं है। यह रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री वालेरी पोल्याकोव के नाम है, जिन्होंने 1990 के दशक में मीर अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 महीने बिताए थे। फिर भी नौ महीने की अवधि उनके शरीर के लिए अंतरिक्ष के चरम वातावरण के सबसे बुरे प्रभावों का अनुभव करने के लिए पर्याप्त थी। अंतरिक्ष की 286-दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को किन-किन शारीरिक परिवर्तनों से गुजरना पड़ा होगा, इसका खुलासा उनके स्वास्थ्य की विस्तृत समीक्षा के बाद ही हो पाएगा। अंतरिक्ष में रहना मनुष्य के लिए सहज नहीं है। अध्ययनों से पता चला है कि अंतरिक्ष में लंबा प्रवास बुढ़ापे की प्रक्रिया को तेज करता है। गुरुत्वाकर्षण की कमी से हृदय और रक्त वाहिकाओं को कम काम करना पड़ता है, जिससे उनमें कमजोरी आ जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों को सामान्य से ज्यादा तेज गति से हड्डियों के घनत्व में कमी, मांसपेशियों में क्षय और कोशिकीय परिवर्तन का भी अनुभव होता है। हड्डियों का घनत्व हर महीने 1-2 प्रतिशत तक कम हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर लौटने पर ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है। इन स्थितियों से निपटने में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करने के लिए आईएसएस विशेष ट्रेडमिल और व्यायाम बाइक से लैस है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों की नकल करने के लिए खास तौर से डिजाइन किए गए रजिस्टेंस बैंड (व्यायाम उपकरण) भी हैं।

ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में आने से डीएनए की क्षति के साथ 'ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस' भी हो सकता है, जिससे आणविक स्तर पर समय से पहले बुढ़ापा आ सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दरअसल पोषक तत्वों और अस्थिर अणुओं का असंतुलन है जो

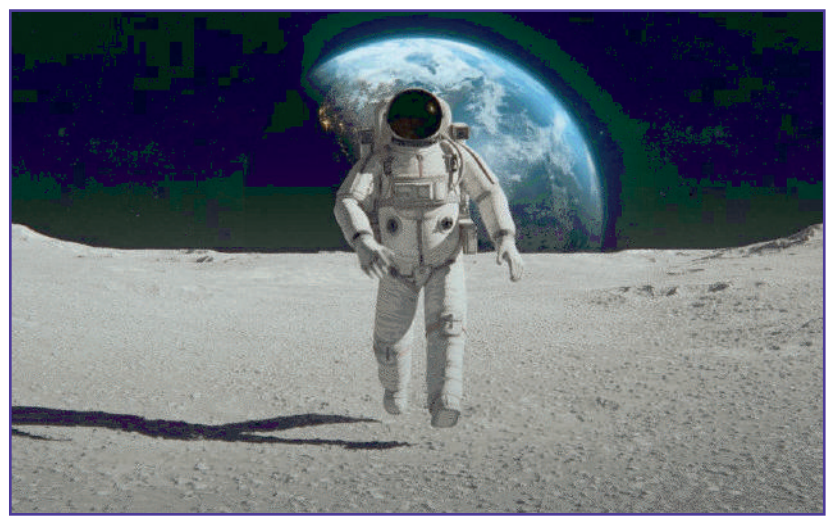

कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा कर रोग उत्पन्न करता है।

गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में शारीरिक द्रव भी सिर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे दृष्टि संबंधी तंत्रिका में सूजन और रेटिना में सिलवटें आ जाती हैं। आंख का पिछला हिस्सा चपटा हो जाता है और मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। इससे स्पेसफ्लाइट-एसोसिएटेड न्यूरो-ऑकुलर सिंड्रोम नामक बीमारी के कारण दृष्टि बाधित हो सकती है। पृथ्वी पर लौटने के बाद मस्तिष्क और आंखों पर दबाव सामान्य स्तर पर वापस आ जाता है, हालांकि इससे होने वाली क्षति कभी-कभी स्थायी हो सकती है। दृष्टि क्षति लंबी अंतरिक्ष यात्रा के सबसे बड़े दुष्प्रभावों में से एक है। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और विकिरण भी श्वेत रक्त कोशिका उत्पादन को बदल सकते हैं, जिससे शरीर की वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। हर्पीज और चिकनपॉक्स जैसे निष्क्रिय वायरस, आईएसएस पर प्रवास के दौरान तनाव और इम्यून सिस्टम के दमन के कारण फिर से सक्रिय हो सकते हैं।

आईएसएस पर जाने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को क्वारंटीन अवधि से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष स्टेशन पर बहुत कम रोगाणु या वायरस हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन में कहा गया है कि अंतरिक्ष स्टेशन बहुत ज्यादा साफ हो सकता है। इसमें रोगाणुओं की कमी के कारण इम्यूनिटी संबंधी समस्याएं, त्वचा संबंधी विकार और अन्य स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आईएसएस से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इस समय 45-दिवसीय रिकंडीशनिंग प्रोग्राम से गुजर रहे हैं जिसमें मांसपेशियों के क्षय को ठीक करने के लिए फिजियोथेरैपी शामिल है।

वहीं नासा का कहना है कि अंतरिक्ष यात्रियों के दल पहले भी अंतरिक्ष में लंबे समय तक रह चुके हैं और धरती पर वापसी के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की परफॉर्मेंस स्थापित मानदंडों के अनुरूप होने की उम्मीद है। पुनर्वास के पहले कुछ दिनों में अंतरिक्ष यात्रियों को चक्कर आएगा क्योंकि उनके शरीर को सीधा रहने के लिए संतुलन बनाए रखने की आदत होगी। कुछ महीनों के भीतर उनकी मांसपेशियों का द्रव्यमान वापस आ जाना चाहिए, जबकि हड्डियों का घनत्व कुछ वर्षों के बाद सामान्य स्तर पर वापस आएगा। उनके शरीर में कुछ परिवर्तनों, जैसे कि दृष्टि दोष, को ठीक करना कठिन हो सकता है।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों पर पड़ने वाले शारीरिक प्रभावों का अध्ययन भविष्य के मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे कि मंगल की एक तरफ़ की यात्रा में लगभग नौ महीने लगते हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले साल जून में 8 दिन के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे लेकिन उनको वहां नौ महीने बिताने पड़ गए क्योंकि उनको वापस लाने वाले बोइंग स्टार लाइनर में खराबी आ गई और किसी न किसी वजह उनकी वापसी टलती गई। लंबे समय तक रहने के बावजूद, विल्मोर और विलियम्स आईएसएस पर सक्रिय रहे। उन्होंने माइक्रोग्रैविटी रिसर्च और स्टेशन के रखरखाव में अपना काम जारी रखा।

ट्रंप और उनके खासमखास मस्क ने इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। उन्होंने बिना किसी सबूत के दावा किया कि विल्मोर और विलियम्स को वापस लाने में देरी राजनीति से प्रेरित थी। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर अंतरिक्ष यात्रियों को अपने हाल पर छोड़ने का आरोप लगाया। इन आरोपों को विशेषज्ञों द्वारा तुरंत खारिज कर दिया गया, जिनमें डेनिश अंतरिक्ष यात्री एंड्रियास मोगेनसेन भी शामिल हैं, जो दो बार आईएसएस के लिए उड़ान भर चुके हैं। मोगेनसेन ने सार्वजनिक रूप से इन दावों की निंदा की और गलत सूचना फैलाने के लिए ट्रंप और मस्क की आलोचना की।

फिर भी अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में देरी हमारे समक्ष कई खड़े सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश और नासा जैसी साधन संपन्न अंतरिक्ष एजेंसी को दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने में नौ महीने क्यों लग गए? इस प्रसंग से एक और बात साफ हो गई है कि अंतरिक्ष में आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अंतरिक्ष विज्ञान में निरंतर प्रगति के बावजूद अंतरिक्ष मिशनों में आज भी अनिश्चितता का तत्व बना हुआ है। मनुष्य को मंगल पर ले जाने का सपना दिखाने वाले मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के दो बड़े रॉकेटों में हाल में हुए विस्फोट यह दर्शाते हैं कि अंतरिक्ष की राह कितनी कठिन है। अंतरिक्ष मिशनों की सफलता के लिए प्रौद्योगिकी भी त्रुटिरहित होनी चाहिए।

छूटती दहलीजें

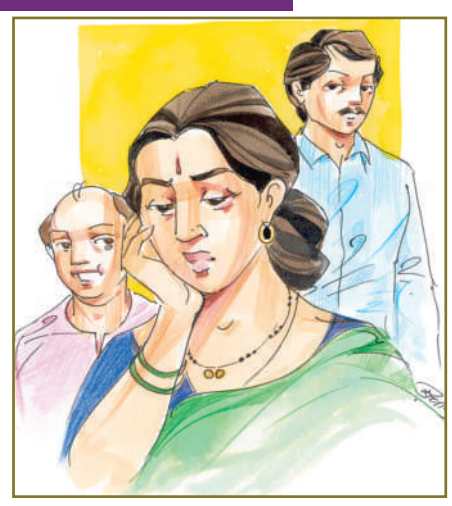

बच्चे जब कुछ समझने लगते हैं तो आमतौर पर घर - घर खेला करते हैं । बचपने में वे अपने बनाए घर यानी मिट्टी-रेत के घरौंदों के लिए आपस में लड़ भी पड़ते हैं। एक-दूसरे के घर तोड़ दिया करते हैं। सब लड़कपने में कभी बचपने में भी । मगर बड़े होते ही तब बहुत कुछ समझने लगते हैं, घर की अहमियत, उसके मतलब और घर के सदस्यों का महत्त्व भी जानने लगते हैं। साथ ही कई बार अपना हक भी बताने लगते हैं। पूरे घर को सिर पर उठा लेना शायद यहीं से शुरू हुआ हो । मगर इस बीच इस बात का अहसास भी घर में जीवन का माहौल बनाता रहता है, घर के सभी लोग खुशहाली और भविष्य की उम्मीद के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का निर्वाह करते हैं ।

उधर शहरों में आने वाले अधिकतर लोग भले ही गांव के घरों को छोड़ कर आए हों या उन्हें बेच कर, पर असल में ये आए तो हैं अपने सपनों को साकार करने। तब ये परम आवश्यक भी दिखता है कि घर के बदले घर बन जाए। रहने से घर की अहमियत होती है । फिर भी यहां-वहां बहुतों को ऊंची इमारतों में बने फ्लैटों में रहते देखा जाता है, जहां प्रायः अपने कम दिखते हैं और बेगाने अधिक। आधे-अधूरे रिश्तों में दिखते लोग अपनी तरह की जिंदगी जीते हैं। देखा जाए तो इनकी एक अलग पहचान होती है, संस्कृति और समाज अलग। इनके सब काम अब आधुनिक जीवनशैली के बीच आमतौर पर आनलाइन होते हैं । वाट्सऐप पर रात-दिन इस तरह रहने वाले लोग करें तो करें क्या और कैसे ? वक्त की 'कद्रदानी' ने इन्हें एक तरह से वक्त काही गुलाम बना लिया है। यहां बात उन घरों की चल रही है जहां 'हम दो हमारे एक या दो' हुआ करते हैं । इन लोगों का खाना-पीना ज्यादातर बाहर होटल-रेस्तरां में होता है। घरों पर इंतजार करने वाला कोई नहीं होता, न इन्हें किसी का इंतजार करना होता है। इस जीवनशैली में रहने वाले ज्यादातर लोगों को यह स्थिति सताती नहीं है, क्योंकि वे इसके अभ्यस्त हो चुके होते हैं ।

कभी-कभी समझ से परे लगता है कि स्त्रियां सारी जिंदगी गुजार देती हैं अपनी बस पति, बच्चे-पोतों में रम कर, पर वे अपने घर - मायके को कभी नहीं भूलतीं। जब तब या कभी किसी बात-बेबात पर या फिर गुस्से में अपनी मां का घर याद हो आता है । घर का बखान करने का अभिप्राय यहां यह है कि आज के दौड़ते-भागते समय में बहुत से लोगों ने घर को दरकिनार कर दिया है। जो काम पहले घरों से शुरू हुआ करते थे, अब बाहर से बाहर हो रहे हैं। बल्कि बाहर ही हो रहे हैं। कई जगहों पर व्यवस्थागत रूप से । शादियां या फिर पार्टियां घर को छोड़ कर भव्य समारोह भवनों में हुआ करती हैं। पैसे के आगे रिश्ते-नाते, रीति-रिवाज यहां तक कि अपनी परंपराएं भी बौनी हो गई लगती हैं। घर को भुला दिया जा रहा है। घर की देहरी पर कभी बारात आती थी या लड़की की विदाई घर से होती थी । अब ये सब बिसरा दिया गया है । शुरू में बच्चों में घर-घर खेलने की बात केवल यह जताने के लिए की गई थी कि घर का अपना कितना महत्त्व और रुतबा होता है ।

महज चारदिवारी में बने स्थान को घर नहीं कह सकते । उसके लिए उसकी छत मतलब मान-मर्यादा होती है। समय- समय पर उसे उचित सम्मान देना पड़ता है। एक गरिमामय उपस्थिति के लिए उसे उसी के रंग में तैयार करना पड़ता 1 यों भी, हम सारी दुनिया में खूब घूम लें, सैर-सपाटा कर आएं, पर जो सुकून, दिल को तसल्ली घर लौट कर आने से मिलती है वह कहीं और नहीं मिलती । घर आते ही जूते- चप्पल, कपड़े-लत्ते कहीं रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले दिनों एक विवाह का निमंत्रण मोबाइल पर आया, जिसे किसी कारणवश समय पर देखा नहीं जा सका। फोन पर जब बताया गया तब मोबाइल खोलना पड़ा। एक परिचित की बिटिया के विवाह का कार्ड था । होटल में विवाह का ब्योरा दर्ज था। शाम के तीन बजे से आठ बजे के बीच। इस बीच विवाह की सभी रस्मे भी होंगी। साथ- साथ नमकीन भी बांटे जाते रहेंगे । आखिरी में खाना । यानी सब काम होटल में। बेचारे घर - देहरी भुला गए । ये बातें अब घर- घर की कही जा सकती है। घर के बच्चे अब बाहर के लगने लगे हैं और बाहर के अपने- पराए में अंतर मिट गया है। पेट पीठ प्रदर्शन के इस जमाने में किस-किस की बताएं, किस-किस की छिपाएं ? समझ नहीं आता। और कहीं-कहीं तो पता भी नहीं रहता ! इस संदर्भ को बढ़ाते हुए इस बात पर गौर किया जा सकता है कि 'समय की कमी' के दौर में फेरों के वक्त को आज के नवयुवक कैसे बर्दाश्त करते हैं, यह समझने वाली बात है । जिन्होंने रीति-रिवाज और परंपराओं को बगल कर दिया हो वे क्या जानें और क्यों जानें ? वैसे भी जिन्होंने मां- बाप को मजबूर कर दिया हो, गांव- जमीन को दरकिनार कर लिया हो मात्र अपने सपनों की खातिर, वे क्या जानेंगे घर के बारे में ? बचपन से जो घर मन-मस्तिष्क में एक मंदिर की तरह जमा था, लगता है जमाने की इस हवा ने घर को बेघर कर दिया है ।

-विजय गर्ग

स्मार्ट खेती खोलती किसान के बेहतर भविष्य की राह

भारत को दुनिया में कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। जो खेती से अपनी विशाल आबादी की खाद्य आवश्यकताएं पूरी करता है। लेकिन देश में खेती करने वाले किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और संसाधनों की सीमित उपलब्धता के चलते कृषि व्यवसाय को समस्याग्रस्त बना दिया है। ऐसे में खेती से जुड़े कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकते हैं। इन तकनीकों के उपयोग से किसानों को खेती के तरीकों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, उनकी पैदावार भी बढ़ सकेगी और लागत भी कम होगी।

खेती में आईओटी तकनीक की मदद से खेतों में विभिन्न सेंसर लगाए जा सकते हैं, जो पहले बताई गई समस्याओं का समाधान करते हैं। ये सेंसर मिट्टी की नमी, तापमान, पीएच स्तर और पोषक तत्वों (एनपीके) की मात्रा को मापते हैं। सेंसर से प्राप्त रियल-टाइम डेटा एआई मॉडल में जाएगा, जिसके जरिये किसान को जानकारी मिल सकेगी कि मिट्टी की स्थिति कैसी है और फसल को पानी या खाद की जरूरत कब है। इससे किसान फसल की सेहत को बेहतर समझ सकते हैं और समय पर उसे सही पोषण दे सकते हैं। इसी तरह एआई और आईओटी के जरिए सिंचाई को भी ऑटोमेटेड किया जा सकता है। सेंसर से प्राप्त डेटा के आधार पर तय किया सकता है कि खेत में कब और कितनी मात्रा में पानी देना है। इससे जल की बर्बादी रुकती है और फसल को जरूरत मुताबिक पानी मिलता है।

तकनीक के प्रयोग से फसलों में लगने वाले रोगों और कीटों का प्रबंधन अब पहले से आसान हो गया है। पहले किसान तब तक इंतजार करते थे जब तक कि बीमारी पूरी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन अब एआई आधारित मोबाइल एप जैसे प्लांटिक्स और एग्रीबोट ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। किसान फसल की फोटो अपलोड करते हैं, और ये ऐप तुरंत बीमारी का पता लगाकर उसका इलाज सुझाते हैं। इससे तुरंत समस्या के बारे में जानकारी मिलती है और समय पर इलाज संभव है।

एआई और आईओटी तकनीकों की मदद से किसान मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी के आधार पर तय कर सकते हैं कि कौनसी फसल लगाना ज्यादा लाभदायक होगा। मशीन लर्निंग मॉडल्स मिट्टी के पोषक तत्वों और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर किसान को सुझाव दे सकते हैं कि कौन-सी फसल लगाने से उत्पादन अधिक होगा और कौन-सी फसल से मुनाफा ज्यादा होगा।

एआई की मदद से मौसम की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इससे किसान पता लगा सकेंगे कि कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ सकता है या कब ठंड पड़ेगी। इस जानकारी के आधार पर फसल की बुआई, कटाई और सिंचाई का सही समय तय कर सकते हैं। मौसम के सटीक पूर्वानुमान के चलते किसान प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं।

आजकल कृषि में ड्रोन तकनीक का भी उपयोग बढ़ रहा है। ड्रोन की मदद से खेतों की निगरानी की जा सकती है। एआई-आधारित इमेज प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग कर किसान जान सकते हैं कि किस हिस्से में बीमारी फैली है या किन क्षेत्रों में अधिक खाद-पानी आदि चाहिये। ड्रोन का उपयोग कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव के लिए भी किया जा सकता है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है।

एआई और आईओटी तकनीकों को कृषि में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार और निजी कंपनियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी कंपनियां भी किसानों के लिए एआई-आधारित समाधान विकसित कर रही हैं। मसलन, आईबीएम ने वेदर कंपनी के जरिये किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देने का काम किया है।

हालांकि एआई और आईओटी खेती के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकते हैं, लेकिन अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। छोटे किसानों की स्मार्टफोन और इंटरनेट तक सीमित पहुंच है। इसके अलावा, एआई और आईओटी आधारित उपकरणों की शुरुआती लागत काफी ज्यादा है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी बाधा बन सकती है। वहीं नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में कई किसानों के लिए उपलब्ध नहीं है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की समस्या भी एआई और आईओटी के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा बन सकती है। उनके लिए सब्सिडी, कम लागत वाले सेंसर और मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान किये जाने की जरूरत है। इससे छोटे किसान भी आधुनिक तकनीकों का लाभ उठा सकेंगे। पूरी तरह से एआई और आईओटी को कृषि में लागू करने के लिए समय, धन और सही रणनीति की आवश्यकता होगी। इसके लिए सब्सिडी, प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी सहायता जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं, ताकि हर किसान इन नवीन तकनीकों का लाभ उठा सके और देश की कृषि उत्पादकता में इजाफा हो।

दिलचस्प जीवन चक्र है साहसी-संघर्षशील जीव का

तटीय केकड़ा सागर तटों पर रहने वाला एक साहसी एवं लडाकू केकड़ा है। यह खतरा निकट होने पर अपने पंजे ऊपर कर लेता है। यह उसकी आत्मरक्षा की मुद्रा होती है, किंतु इसे देखने पर ऐसा लगता है मानो यह लड़ाई के लिए तैयार हो। तटीय केकड़ों की अनेक जातियां हैं, जिनमें यूरोप का तटीय केकड़ा प्रमुख है। यह यूरोप के पश्चिमी भागों के सागर तटों पर बहुतायत से मिलता है। यूरोप का तटीय केकड़ा अटलांटिक महासागर में उत्तर अमेरिका के सागर तटों पर भी केपकाड से न्यूजर्सी तक देखा जा सकता है। यहां इसे हरा केकड़ा कहते हैं। यूरोप तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाले तटीय केकड़ों में हरा रंग मुख्य रूप से नर का होता है। वयस्क मादाओं का रंग प्रायः नारंगी होता है। इनके बच्चों के रंगों और डिजाइनों में काफी विविधता होती है। कुछ काले होते हैं, तो कुछ हरे, कुछ सफेद-लाल होते हैं, तो कुछ लाल-काले होते हैं। ये बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, इनके रंगों की विविधता कम होती जाती है, और वयस्क होते-होते यह विविधता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तटीय केकड़ों की कुछ जातियां दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के सागर तटों पर, उत्तरी अफ्रीका के सागर तटों पर, तथा श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि के सागर तटों पर भी पाई जाती हैं।

तटीय केकड़ा दलदली या चट्टानी जगह पर रहना पसंद करता है। यह ताजे पानी में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। दिन के समय यह चट्टानों की दरारों में छिपा रहता है और रात में सक्रिय होता है। ज्वार के समय यह सागर तट पर आ जाता है, और ज्वार के लौट जाने पर भी वहीं बना रहता है। सर्दियों में ज्वार के साथ वापस लौट जाता है। यह जमीन और पानी दोनों में आसानी से रह सकता है, लेकिन यह अच्छा तैराक नहीं है। इसकी शारीरिक संरचना वास्तविक केकड़े के समान होती है। यह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के साथ ही सीधे हवा से भी सांस ले सकता है। नर तटीय केकड़े का पेट पांच भाग वाला होता है, जबकि मादा के पेट में सात भाग होते हैं।

तटीय केकड़ा एक अच्छा शिकारी जीव है, जो उन सभी जीवों का शिकार करता है जिन्हें यह मार सकता है। शिकार के लिए यह अपने पैरों के चिमटे का उपयोग करता है। इसके पैरों के चिमटे बहुत मजबूत और ताकतवर होते हैं। तटीय केकड़ा शिकार न मिलने पर सड़ा-गला मांस भी खा लेता है। इसमें बाह्य समागम और बाह्य निषेचन पाया जाता है। तटीय केकड़ों में पूरे वर्ष समागम और प्रजनन चलता रहता है, लेकिन फरवरी में इनमें प्रजनन चरम सीमा पर होता है।

मादा तटीय केकड़ा अपने निषेचित अंडों को परिपक्व होने तक अपने पेट के नीचे रखती है। वसंत और गर्मियों के आरंभ में अंडे फूटते हैं और इनसे बड़ी संख्या में लार्वे निकलते हैं। तटीय केकड़े के लार्वे जन्म देने वाले माता-पिता से पूरी तरह भिन्न होते हैं, और चार अवस्थाएं पार करने के बाद छोटे से वयस्क केकड़े जैसे बन जाते हैं। इसका विकास बड़ी धीमी गति से होता है। इसके दो सेंटीमीटर लंबे बच्चे के शरीर पर पीले, लाल, सफेद, काले आदि रंग और विभिन्न प्रकार की डिज़ाइनों का पाया जाना सामान्य है। जैसे-जैसे ये बढ़ते हैं, इनके रंगों और डिज़ाइनों की विविधता कम होती जाती है। तटीय केकड़ा का लार्वा छह बार निमोचन करता है, और अंतिम बार निमोचन करने के बाद बच्चा तटीय केकड़ा जैसा दिखने लगता है। अब ये जमीन पर चल सकता है तथा अपने पैरों के तीसरे और चौथे जोड़े को अपने आवरण पर रखकर तैर सकता है। तटीय केकड़ा का लार्वा बच्चा केकड़ा बनने के बाद भी निमोचन करता रहता है। इसके बाद यह एक बार विशेष निमोचन करता है, और इसके प्रजनन अंग निकलते हैं। बच्चा केकड़ा बनने के बाद भी 10 से 11 बार निमोचन करता है। मादा तटीय केकड़े के 6.5 सेंटीमीटर का हो जाने और नर के 7.5 सेंटीमीटर होने पर निमोचन बंद हो जाता है। ये गर्मियों में अधिक निमोचन करते हैं।

निमोचन के समय यह अपने शरीर में अपने वजन का 70 प्रतिशत तक पानी भर लेता है, जिससे इसका शरीर फूल जाता है और ऊपर का आवरण अनेक जगहों से चटक जाता है, फिर धीरे-धीरे मरकर शरीर से अलग हो जाता है। तटीय केकड़े का नया आवरण बहुत कोमल होता है। अतः इसे उस समय तक छिपकर रहना पड़ता है, जब तक यह कठोर नहीं हो जाता। तटीय केकड़ा स्वजाति भक्षी होता है। अगर यह अपने शत्रुओं से बच जाए तो यह लगभग तीन वर्ष की आयु तक जीवित रहता है, लेकिन मानव से नहीं बच पाता। यूरोप के अनेक देशों के लोग तटीय केकड़े को बहुत शौक से खाते हैं।

-विजय गर्ग

-कैसे प्रासंगिक बनेगी कांग्रेस

कांग्रेस का गुजरात अधिवेशन सम्पन्न हो गया। गुजरात में जनवरी, 1961 के बाद, यानी 64 लंबे सालों के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है। चूंकि महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष होने की 100वीं सालगिरह है और सरदार पटेल की 150वीं जयंती का वर्ष है, लिहाजा विरासत की जमीन पर दोबारा खड़े होने और उसके आधार पर राजनीति करना तय किया गया। सवाल है कि आज ही गांधी-पटेल सरीखे महानायकों के गढ़ की याद क्यों आई, जबकि लोकतंत्र, समाजवाद, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता आदि कांग्रेस के परंपरागत वैचारिक मूल्य आज धुंधले हैं। उनके जुमले ही सुनाई देते हैं। गुजरात 1995 से भाजपा का राजनीतिक गढ़ है। भाजपा लगातार 7 चुनाव जीत चुकी है। मौजूदा सदन में कांग्रेस के मात्र 12 विधायक हैं और गुजरात में भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को ध्वस्त करने की हुंकार कांग्रेस ने भरी है। कांग्रेस के सामने प्रासंगिक और स्वीकार्य होने की बेहद गंभीर चुनौती है। अधिवेशन के उपसंहार में विचारधारा और राष्ट्रवाद पर डटे रहने का आह्वान निहित है, लेकिन पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दलितों, मुसलमानों के अलावा ओबीसी को भी कांग्रेस के साथ जोडने की बात कही है। ब्राह्मण लगभग भाजपा के पाले में जा चुके हैं। दरअसल 1990 में मंडल आयोग की रपट पारित करने के बाद ओबीसी कांग्रेस का समर्थक-वर्ग रहा ही नहीं। पिछड़े और अति पिछड़े स्थानीय और क्षेत्रीय दलों के बीच बंट गए अथवा प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र-बिंदु बनने के बाद ओबीसी भाजपा की ओर धुरवीकृत हो गए। कांग्रेस ओबीसी के बीच अपना जनाधार कैसे बनाएगी, अधिवेशन के बावजूद यह स्पष्ट नहीं हुआ। इंदिरा गांधी के दौर में जब कांग्रेस सत्तारूढ़ होती थी, तब भी दलित, मुसलमान, सवर्ण, आदिवासी कांग्रेस के जनाधार होते थे, लेकिन पिछड़े कम ही कांग्रेस के साथ थे। अब कांग्रेस का नए सिरे से पुनरोत्थान कैसे होगा और वह पहले की तरह स्वीकृत और स्थापित पार्टी कैसे बनेगी, इस पर दावे तो खूब किए गए हैं, नेताओं-कार्यकर्ताओं का जोशीला आह्वान भी किया गया है, लेकिन पार्टी के जिला अध्यक्षों को ताकतवर बनाने से ही यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रवाद आरएसएस-भाजपा का स्वीकार्य विचार है।

महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद बिल्कुल ही अलग है। कमोबेश कांग्रेस ने गांधी के राष्ट्रवाद को नहीं अपनाया है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद क्या जातीय जनगणना से ही तय होगा? जातीय जनगणना और संविधान का फर्जी नेरेटिव कांग्रेस, सपा और विपक्ष के एक तबके ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचारित किया था। खासकर दलितों में भ्रम फैलाया गया कि यदि भाजपा-एनडीए को 400 सीटें मिल गईं, तो सरकार संविधान को बदल सकती है। यदि संविधान के कुछ विशेष प्रावधान खत्म किए गए, तो आरक्षण भी समाप्त हो सकता है। केंद्र में भाजपा-एनडीए की सरकार है और संविधान-आरक्षण के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, लिहाजा जो दलित कांग्रेस की ओर गए थे, अब लौट कर अपना नया नेतृत्व तलाश रहे हैं। दलित भाजपा की ओर भी लौट रहे हैं। कांग्रेस के सामने यह भी गंभीर चुनौती रहेगी। आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि देश के 5 राज्यों की विधानसभाओं में उसका कोई भी विधायक नहीं है। 9 राज्यों की विधानसभाओं में 10 से भी कम विधायक हैं। कांग्रेस के 3 ही मुख्यमंत्री हैं और तीन गठबंधन सरकारों में वह शामिल है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री चुने गए, तब भी कांग्रेस के 12 मुख्यमंत्री होते थे। गौरतलब यह है कि यह गांधी की कांग्रेस भी नहीं है। इंदिरा गांधी के दौर में 1966 में पार्टी दोफाड़ हो गई थी और इंदिरा ने अपने नाम से कांग्रेस बनाई थी। वही कांग्रेस आज हमारे सामने है और प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल की विरासत को भाजपा के पाले में ला चुके हैं। विरासत की लड़ाई में जनता क्या तय करती है और किसे ज्यादा प्रासंगिक पार्टी के तौर पर स्वीकार करती है, अब यह सबसे अहम यक्ष-प्रश्न है। कांग्रेस को अपने संगठन को चुस्त-दुरुस्त करना होगा और अहम मसलों पर सरकार को घेरने की ठोस रणनीति बनानी होगी।

सरकारी स्कूलों को बन्द करने की बजाय उनका रुतबा बढ़ाये

भारत में सरकारी स्कूल सामाजिक समानता और शिक्षा के अधिकार के प्रतीक हैं, लेकिन बजट कटौती, ढांचागत कमी और शिक्षकों की अनुपलब्धता ने इनकी साख गिराई है। हरियाणा इसका ताजा उदाहरण है, जहाँ 2022 में 292 स्कूल बंद हुए, और 2024 में 800 और स्कूलों को बंद करने की योजना है। सरकारें नामांकन की कमी को आधार बनाकर स्कूल बंद कर रही हैं, लेकिन इसकी असली वजह व्यवस्थागत लापरवाही है। स्कूलों को बंद करने के बजाय उनका पुनर्निर्माण, शिक्षक भर्ती, आधारभूत ढांचे में सुधार और सामाजिक भागीदारी के ज़रिए मजबूत किया जाना चाहिए। दिल्ली का मॉडल इस दिशा में प्रेरणास्रोत है। शिक्षा को अधिकार मानकर सरकारी स्कूलों की गरिमा बहाल करना लोकतंत्र की आत्मा को पुनर्जीवित करने जैसा है। स्कूल बंद मत कीजिए—उन्हें सम्मान और संसाधन दीजिए।

प्रियंका सौरभ

भारत जैसे लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय की परिकल्पना वाले देश में सरकारी स्कूल केवल शिक्षा के केंद्र नहीं, बल्कि समान अवसर की उम्मीद भी होते हैं। ये वे स्थान हैं जहाँ समाज का सबसे कमजोर तबका, सबसे कमज़ोर बच्चा भी सपना देख सकता है—आगे बढ़ने का, कुछ बनने का। पर दुर्भाग्यवश आज सरकारें इन्हें बोझ मानने लगी हैं। कहीं स्कूलों का विलय हो रहा है, कहीं उन्हें निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। सवाल यह है कि जब देश की रीढ़ मजबूत करनी हो, तो उसे काटा क्यों जा रहा है?

सरकारी स्कूलः व्यवस्था की रीढ़

भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है, पर अधिकार सिर्फ कागज़ पर नहीं, ज़मीनी हकीकत पर टिकते हैं। सरकारी स्कूल गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय बच्चों के लिए एकमात्र विकल्प हैं। निजी स्कूलों की ऊँची फीस, प्रवेश प्रक्रिया और बाज़ारी सोच उन्हें आम आदमी की पहुँच से बाहर कर देती है। ऐसे में सरकारी स्कूल न केवल शिक्षा देते हैं, बल्कि सामाजिक समरसता और बराबरी की भावना भी गढ़ते हैं।

क्यों गिरा सरकारी स्कूलों का रुतबा?

सरकारी स्कूलों की छवि को योजनाबद्ध तरीके से खराब किया गया। दशकों तक उन्हें बजट की मार झेलनी पड़ी। शिक्षकों की भारी कमी, ढांचागत बदहाली, पढ़ाई में रुचि की कमी और प्रशासनिक उपेक्षा ने सरकारी स्कूलों को रसातल की ओर धकेला। दूसरी ओर, निजी स्कूलों को लगातार बढ़ावा दिया गया—टैक्स में छूट, जमीन में रियायतें, नियमों में नरमी। सरकारी स्कूल के बच्चे को 'कमतर' और प्राइवेट स्कूल के बच्चे को 'सक्षम' मानना एक मानसिक रोग बन गया।

बंद करने की नीतिः हरियाणा का उदाहरण

हरियाणा में सरकारी स्कूलों को बंद करने की

नीतिगत प्रक्रिया इसका जीवंत उदाहरण है। वर्ष 2022 में राज्य में कुल 292 सरकारी स्कूलों को बंद या एकीकृत किया गया, जिनमें से अधिकांश में छात्रों की संख्या 25 से कम या शून्य थी। यह आँकड़ा राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यह रुकने वाला नहीं है।

जनवरी 2024 में सरकार ने घोषणा की कि वह उन 800 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की योजना बना रही है जहाँ छात्रों की संख्या 20 से कम है। इनमें पढ़ने वाले लगभग 7,349 बच्चों को अन्य निकटवर्ती स्कूलों में भेजा जाएगा, और परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। सवाल यह है कि यह समाधान है या सिरदर्द को सिर हटाकर खत्म करने वाली सोच?

समाधानः बंद नहीं, बदलाव

अगर सरकारी स्कूलों में समस्या है, तो उन्हें बेहतर बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। निम्नलिखित कदम इस दिशा में निर्णायक हो सकते हैं। 1. शिक्षकों की नियमित और पारदर्शी भर्तीः शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी बाधा है। योग्य और प्रेरित शिक्षक ही किसी भी स्कूल की नींव होते हैं। 2. बुनियादी ढांचे में निवेशः साफ-सुथरी इमारत, शौचालय, पीने का पानी, लाइब्रेरी और डिजिटल सुविधाएं—ये बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करते हैं। 3. स्थानीय समुदाय की भागीदारीः स्कूल प्रबंधन समितियों को मज़बूत बनाकर स्थानीय लोगों को फैसलों में शामिल किया जाए। 4. गुणवत्ता की निगरानी और मूल्यांकनः सिर्फ नामांकन नहीं, शिक्षण की गुणवत्ता पर भी नज़र रखी जाए। 5. मीडिया में सकारात्मक छवि निर्माणः सरकारी स्कूलों की सफलता की कहानियाँ सामने लाई जाएं ताकि उनकी साख बहाल हो।

दिल्ली मॉडलः एक प्रेरणा

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकारी स्कूलों के कायाकल्प की दिशा में उदाहरण पेश किया है। न केवल नई इमारतें बनीं, बल्कि शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई, स्कूलों को साफ-सुथरा और तकनीक से लैस बनाया गया, और सबसे बड़ी बात—सरकार के मंत्री खुद स्कूलों में जाकर निरीक्षण करने लगे। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में रिज़ल्ट भी बेहतर हैं और आत्मविश्वास भी।

शिक्षा को बाज़ार नहीं, अधिकार समझिए

शिक्षा को व्यापार बना देने से एक वर्ग आगे तो बढ़ेगा, पर बहुसंख्यक वर्ग पीछे ही रह जाएगा। इससे सामाजिक विषमता और गहरी होगी। सरकार की भूमिका तटस्थ नहीं, सक्रिय होनी चाहिए। उसे चाहिए कि वह शिक्षा को एक सामाजिक दायित्व माने, न कि राजस्व की वस्तु।

सरकारी स्कूलों की साख बहाल करना, लोकतंत्र की साख बहाल करना है

अगर सरकारी स्कूल बंद होते हैं, तो यह केवल शिक्षण संस्थानों का बंद होना नहीं है, यह उस विचार का पतन है जिसमें हर बच्चे को समान अवसर मिलने चाहिए थे। यह संविधान में आस्था को डगमगाने जैसा है। यह लोकतंत्र की आत्मा पर आघात है।

स्कूल मत बंद करो, सोच बदलो

सरकारी स्कूलों को बंद करना आसान है, लेकिन एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बंद हो जाएगा। यह वक्त है सोच बदलने का, दिशा बदलने का। हमें चाहिए कि सरकारी स्कूलों को गर्व का केंद्र बनाएं—ऐसे संस्थान जहाँ शिक्षा का अधिकार नहीं, सम्मान मिले। जहाँ बच्चा न ये पूछे कि वो प्राइवेट स्कूल से है या सरकारी से, बल्कि ये पूछे कि वो सीख क्या रहा है, सोच क्या रहा है, और आगे क्या कर सकता है।

बाबा साहब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल पर विशेष...

बाबा साहेब : संविधान के शिल्पकार, सामाजिक न्याय के पुरोधा

प्रदीप कुमार वर्मा

दलितों के मसीहा के नाम से देश और दुनिया मे चर्चित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की पहचान एक कानूनविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में रही हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने बतौर कानूनविद भारत के संविधान की रचना की तो दलित एवं वंचितों को उनके हक और हकूक दिलाने के लिए वह सामाजिक न्याय के पुरोधा भी बने। बाबा साहब अंबेडकर की सोच कितनी दूरगामी थी, इसका अंदाजा इस बात से लाया जा सकता है कि संविधान के लागू होने के 75 वर्षों के बाद भी संविधान की मूल भावना में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। भारत का संविधान आज भी शासन के संचालन से लेकर दलित एवं वंचितों के अधिकारों के संरक्षण का काम बखूबी कर रहा है।

संविधान निर्माता बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में स्थित सैनिक छावनी में हुआ था। वह अपने माता-पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर तैनात थे। बाबासाहेब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वह अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित हुए। वर्ष 1907 में मैट्रिक तथा स्नातक की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से की। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी। वर्ष 1913 में डॉ. अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने वाले एक विद्वान के रूप में चुना गया।

यह उनके शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सामाजिक सुधारों के पुरोधा के रूप में डॉ. अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता विकसित करने एवं हिन्दू समाज में समानता लाने के लिए हिन्दू कोड बिल का समर्थन किया। इसके साथ ही आर्थिक सुधारों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उन्होंने कृषि व्यवस्था में सुधार के तहत भूमि के समान वितरण, कृषि श्रमिकों, कृषि कर तथा सम्पत्ति कर पर भी अपना उपयोगी मत दिया। बाबा साहेब का यह भी मानना था कि औद्योगिकरण के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। इसलिए उन्होने औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया। श्रमिकों की हालात को देखते हुये सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, बीमा योजना, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, गरीबी, बेरोजगारी, बेगारी एवं नशाबन्दी आदि पर अपने विचार दिए।

कालांतर में इन्ही विचारों पर अमल करते हुए देश में अनेक कानून बने। इसके अलावा बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन को बाबासाहेब द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर किया गया था। बाबा साहेब का मानना था कि मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। विकास के साथ-साथ सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति केवल जनसाधारण की शिक्षा से ही संभव है। उन्होंने 'शिक्षित करो, आंदोलन करो, संगठित करो' का नारा दिया। वर्ष1945 में स्थापित पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के सहयोग से वंचितों के उत्थान के लिए कई स्कूल, कॉलेज, छात्रावास और अन्य शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए। यह डॉ. साहब के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था संविधान व नीति निर्देशक तत्वों में की गई।

उधर, अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा में भी बाबा साहेब ने ₹दलित उत्थान और संवर्धन₹ को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा। दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने 15 अगस्त 1936 को "स्वतंत्र लेबर पार्टी" का गठन किया। जब वर्ष 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम में बदलाव करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया, तब डा अंबेडकर ने इसकी आलोचना की। उनका दृष्टिकोण था कि नाम बदलने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसी क्रम में वर्ष 1942 में वह भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद वर्ष 1946 में उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया। आजादी के बाद वर्ष 1947 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में उन्हें कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया लेकिन वर्ष 1951 में कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

यह सही है कि तत्कालीन भारतीय समाज और शिक्षा और जाति भेदभाव की वीडियो में जकड़ा हुआ था। राजाराम मोहन राय से लेकर स्वामी दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द ओर महात्मा गाँधी जैसे प्रखर समाज सुधारक भी हुए किन्तु सदियों से अभिशप्त, अस्पृश्यों और दलितों के उद्धार के लिए दलितों में से ही नेतृत्व उभारने का मार्ग डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने दिखाया।

उन्होंने सामंती असमानता और जाति व्यवस्था की सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। वह भारतीय समाज को जाति व्यवस्था की बुराइयों से भी मुक्त करना चाहते थे। डॉ. अंबेडकर का समूचा जीवन यह दर्शाता है कि वह विद्वान और कर्मशील व्यक्ति थे। बाबा साहेब ने अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून, दर्शन और समाजशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना जीवन समानता, भाईचारे और मानवता के लिए समर्पित किया। वर्ष 1956 में 06 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। भले ही बाबासाहेब आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी शिक्षा, उनके विचार तथा दलित उत्थान के लिए किए गए उनके कार्य लोगों के हृदय में सालों साल तक एक मधुर स्मृति के रूप में चिरस्थाई रहेंगे।

कटक में मुस्लिम मेला; वक्फ विधेयक का कड़ा विरोध

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : वक्फ विधेयक के खिलाफ मुसलमान रैली में शामिल हुए। कटक की एक मस्जिद में सैकड़ों मुसलमान एकत्र हुए। मुसलमानों ने संशोधित विधेयक के कुछ प्रावधानों का विरोध किया है। इसलिए इनमें से कुछ नियमों में संशोधन की मांग की गई है। मुसलमानों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।अगले शनिवार को मुसलमान इसके खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही कटक जिला एसपी कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मांग पत्र कटक जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। इससे पहले भी आरोप लग चुके हैं कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 और तीन तलाक जैसे वक्फ मुद्दों पर मनमानी कर रही है। इस बीच, नवीन पटनायक ने भी धमकी दी है कि अगर दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया गया तो वे आगे भी कदम उठाएंगे।

"जयंती का शोर, विचारों से ग़ैरहाज़िरी, "मूर्ति की पूजा, विचारों की हत्या", "हाथ में माला, मन में पाखंड"

बाबा साहेब की विरासत पर सत्ता की सियासत, जयंती या सत्ता का स्वार्थी तमाशा?

बाबा साहब के विचारों—जैसे सामाजिक न्याय, जातिवाद का उन्मूलन, दलित-पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी, और संविधान की गरिमा की रक्षा—को आज के राजनेता पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। राजनीतिक दल केवल वोट बैंक के लिए अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, जबकि वे उनके विचारों से कोसों दूर हैं। जिन मुद्दों के लिए बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया—जैसे आरक्षण की सामाजिक भूमिका, जातिगत जनगणना, आर्थिक आधार पर प्रतिनिधित्व—उन्हें आज भी दरकिनार किया जा रहा है। संसद और विधानसभाओं में पूंजीपतियों, सेलेब्रिटीज़ को भेजा जा रहा है, जबकि वंचित वर्ग हाशिए पर है। क्या बाबा साहब की आत्मा तब तक संतुष्ट हो सकती है जब तक उनके सपनों का भारत साकार न हो? यदि सच में अंबेडकर को श्रद्धांजलि देनी है, तो उनके विचारों को व्यवहार में लाना होगा—वरना यह सब केवल एक दिखावा और ढोंग ही रह जाएगा।

प्रियंका सौरभ

देश भर में आज बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिरों की घंटियों की तरह मंचों पर माइक बज रहे हैं, फूलों की माला और भावुक भाषणों की बाढ़ है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल लगातार मन को कुरेदता है — क्या यह श्रद्धांजलि है या सत्ता की साधना?

बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के महू में हुआ था। वे महार जाति से थे, जिसे अछूत समझा जाता था। सामाजिक बहिष्कार और अपमान के बीच उन्होंने शिक्षा हासिल की और कोलंबिया विश्वविद्यालय व लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। यह उपलब्धि अपने आप में उस समय के भारत में एक क्रांति थी।

बाबा साहेब ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोला और 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया — एक ऐसा धर्म जो समता, करुणा और ज्ञान की राह दिखाता है। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं — बशर्ते उन्हें ज़िंदा रखा जाए।

आज जब हम संसद और विधानसभाओं की तरफ नज़र डालते हैं, तो पाते हैं कि वहां बड़े पैमाने पर पूंजीपति, अभिनेता, खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन जो बहुजन समाज सत्ता की सीढ़ी बनता है, उसे नीचे ही रहने दिया जाता है। जातिगत जनगणना से बचने वाली सरकारें, सामाजिक न्याय को स्थायी नीति में बदलने को तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि समाज में गहराई से असमानता बनी हुई ह

बाबा साहब की जयंती पर करोड़ों रुपये खर्च कर देना, बड़ी रैलियां और पोस्टर लगवा देना, उनकी मूर्तियों को फूलों से ढक देना — क्या यही श्रद्धा है? क्या ये वही लोग नहीं हैं जो बाबा साहब की किताबें कभी पढ़ते तक नहीं? क्या ये वही सियासी दल नहीं हैं जिनकी नीतियां प्रत्यक्ष रूप से संविधान की आत्मा के विरुद्ध जाती हैं?

यह ढोंग तभी रुकेगा जब हाथी के दांत खाने और दिखाने के एक कर दिए जाएं। जब कथनी और करनी में फर्क मिटेगा। और जब शासन सत्ता में सभी को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी — तभी हम कह सकेंगे कि हमने बाबा साहब को सही मायनों में श्रद्धांजलि दी है।

जिस बाबा साहेब ने भारत के सबसे दबे-कुचले, हाशिए पर पड़े वर्गों को

आ वा ज
दी, संविधान में
उनके अधिकार सुनिश्चित किए, उन्हीं के नाम पर आज वही लोग जयंती मना रहे हैं जिन्होंने उनके विचारों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

बाबा साहेब ने स्पष्ट कहा था: ₹मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं — यह मेरे वश में है।₹ इस ऐतिहासिक उद्घोषणा को समझने के बजाय, राजनेताओं ने उन्हें मूर्तियों तक सीमित कर दिया। संविधान, जिसे उन्होंने दलितों, पिछड़ों और गरीबों की रक्षा के लिए लिखा था, उसे आज बेतरतीब तरीके से तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है।

बड़े दुख की बात है कि जिन दलों का जन्म ही दलितों और पिछड़ों के हक के लिए हुआ था, वे आज या तो सत्ता के लालच में चुप हैं या डर के मारे मौनव्रत धारण किए हुए हैं। बसपा जैसे दल बाबा साहेब का नाम लेकर सत्ता में आए, लेकिन आज उनके सिद्धांतों की रक्षा में सबसे पीछे हैं।

सिर्फ चुनावी रणनीति बनकर रह गया है बाबा साहेब का नाम। आरक्षित सीटों से विधायक-सांसद बनने वाले लोग अपने-अपने दलों की गुलामी में मग्न हैं। वे दलित हितों पर हो रहे प्रहारों को मूकदर्शक बनकर देख रहे हैं। ऐसे में एक साधारण नागरिक के तौर पर मैं, विनेश ठाकुर, इन सत्ता-भोगी प्रतिनिधियों की कठोर निंदा करता हूँ।

आज जो लोग बाबा साहेब को याद कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश ने उनके विचारों पर एक कदम भी चलने का साहस नहीं दिखाया। जातिगत जनगणना, जनसंख्या के अनुपात में सत्ता में हिस्सेदारी, शिक्षा और रोज़गार में बराबरी जैसे मुद्दे आज भी लंबित हैं। इसके बजाय गरीबों को फ्री राशन देकर खुश करने की नीति अपनाई जा रही है — स्थायी रोजगार और गरिमा भरे जीवन की जगह भीख सरीखा जीवन दिया जा रहा है।

लोकसभा और विधानसभाओं में बड़े-बड़े उद्योगपति, अभिनेता और खिलाड़ी पहुँचते हैं, लेकिन जिनके वोटों से सरकारें बनती हैं — दलित, आदिवासी, ओबीसी — वे आज भी हाशिए पर हैं। बाबा साहेब की असली विरासत की हत्या हो चुकी है और अब उनकी जयंती सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट बन गई है।

उनकी जीवनी सबको मालूम है — 14 अप्रैल 1891, महू (मध्यप्रदेश) में जन्म, अछूत मानी जाने वाली महार जाति से संबंध, बचपन में भेदभाव का शिकार, लेकिन अद्वितीय प्रतिभा से दुनिया को चौंका देने वाला व्यक्तित्व। उन्होंने पूरी दुनिया से ज्ञान अर्जित कर भारत के लिए एक ऐसा संविधान लिखा जो हर नागरिक को समानता, न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर सामाजिक विद्रोह किया। वे जीवन भर छुआछूत, जातिवाद, असमानता और राजनीतिक उपेक्षा के खिलाफ संघर्ष करते रहे। लेकिन आज, उनके नाम पर सिर्फ भीड़ जुटाई जा रही है, विचार नहीं। राजनीतिक दलों से मेरा सीधा सवाल है — क्या आपने सामाजिक न्याय के लिए कोई ठोस कदम उठाया? जवाब स्पष्ट है: शून्य।

यदि वास्तव में आप बाबा साहेब की सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो एक वर्ष के लिए धार्मिक आयोजनों, दिखावटी अभियानों और मूर्ति अनावरणों का बजट काटिए। उस पैसे से सभी जातियों के लिए आर्थिक आधार पर न्याय की व्यवस्था कीजिए। सत्ता में जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित कीजिए। 50% कमीशनखोरी बंद करिए, निजीकरण की लहर पर विराम लगाइए।

अगर आप यह कर सकें, तो यकीन मानिए — बाबा साहेब की आत्मा कहेगी, ₹अब तुमने मेरे विचारों को सिर्फ याद नहीं किया, बल्कि जिया है।₹ वरना, हाथी के दिखाने और खाने के दांतों में फर्क बना रहेगा — और यह फर्क ही एक दिन लोकतंत्र को निगल जाएगा।

"लोकतांत्रिक भारत: हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेवारी" जनतंत्र की जान: सजग नागरिक और सतत भागीदारी

लोकतंत्र केवल अधिकारों का मंच नहीं, बल्कि नागरिकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का साझेधार भी है। भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका केवल वोट देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्हें न्याय, समानता, संवाद, स्वच्छता, कर भुगतान, और संस्थाओं के प्रति सम्मान जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती सत्ता पर निगरानी, सूचनाओं की सत्यता, और सामाजिक सहभागिता से आती है। जब नागरिक अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, तब लोकतंत्र केवल एक दिखावटी ढांचा रह जाता है। अतः लोकतंत्र को जीवित, सशक्त और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हर नागरिक को आत्मनिरीक्षण करते हुए यह पूछना होगा: "क्या मैं केवल अधिकार चाहता हूँ या जिम्मेदार भी हूँ?"

डॉ. सत्यवान सौरभ

लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, एक जीवनशैली है। यह नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय का वादा करता है, लेकिन साथ ही उनसे सजगता, जागरूकता और जिम्मेदारी की अपेक्षा भी करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर क्या हम इसके सबसे जिम्मेदार नागरिक भी हैं? क्या हमने लोकतंत्र को केवल एक वोट देने का औज़ार मान लिया है या फिर हम इसके गहरे मूल्यों और कर्तव्यों को समझते हैं?

लोकतंत्र: अधिकार नहीं, दायित्व भी

भारतीय संविधान ने हमें कई मौलिक अधिकार दिए हैं — बोलने की आज़ादी, धर्म की स्वतंत्रता, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। पर संविधान ने केवल अधिकार नहीं दिए, कर्तव्यों की भी नींव रखी। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इनमें राष्ट्र की अखंडता की रक्षा, संविधान का सम्मान, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना जैसे पहलू शामिल हैं।

पर विडंबना यह है कि अधिकांश नागरिक अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन। सड़क पर गंदगी देखकर हम सरकार को कोसते हैं, पर खुद कचरा फेंकने से नहीं चूकते। टैक्स चोरी को 'चालाकी' समझते हैं, पर सरकार की नीतियों को 'भ्रष्ट' कहते हैं। यही वह मानसिकता है जो लोकतंत्र को खोखला करती है।

लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका

एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी संभव है जब उसके नागरिक सक्रिय, जागरूक और नैतिक हों। लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, चुनावों के बीच की जिम्मेदारियों से भी चलता है। नागरिकों को सरकार की नीतियों पर नजर रखनी चाहिए, मीडिया की सच्चाई को परखना चाहिए, और गलत को गलत कहने का साहस दिखाना चाहिए। आज जब सोशल मीडिया सूचनाओं का सबसे तेज़ माध्यम बन गया है, वहां झूठ और नफरत तेजी से फैल रही है। एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका है कि वह सूचना की सत्यता की जांच करे, नफरत की राजनीति का शिकार न बने और डिजिटल विवेक से कार्य करे।

न्याय, समानता और संवाद की संस्कृति

लोकतंत्र की बुनियाद न्याय और समानता पर टिकी होती है। लेकिन आज भी जाति, धर्म, वर्ग और भाषा के आधार पर भेदभाव जारी है। गांवों में दलितों को मंदिरों में प्रवेश से रोका जाता है, शहरों में मुस्लिमों को मकान नहीं दिया जाता, आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जाती हैं। यह सब लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह समाज में समानता और सह-अस्तित्व की संस्कृति को बढ़ावा दे। मतभेद होना लोकतंत्र का सौंदर्य है, पर मतभेद को मनभेद में बदलना उसकी कमजोरी है। संवाद, सहिष्णुता और सहमति की भावना ही लोकतंत्र को जीवंत रखती है।

सत्ता पर निगरानी और जवाबदेही

लोकतंत्र में सत्ता की असली ताकत जनता के हाथों में होती है। लेकिन अगर जनता ही अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हो जाए, तो सत्ता बेलगाम हो जाती है। आज हमें नेताओं से सवाल पूछने की जरूरत है — उनके वादों, कार्यों और नीतियों पर। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? या फिर जाति, धर्म और व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर उन्हें आंख मूंदकर समर्थन देते हैं? एक लोकतांत्रिक नागरिक को न तो सत्ता से डरना चाहिए, न ही अंधभक्ति में डूबना चाहिए। जवाबदेही, पारदर्शिता और जनसुनवाई की मांग करना हर नागरिक का दायित्व है। लोकतंत्र में शासक नहीं, प्रतिनिधि होते हैं — और प्रतिनिधि को जवाब देना होता है।

सरकारी संस्थाओं और कानून का सम्मान

लोकतंत्र की नींव उसकी संस्थाओं से मजबूत होती है — न्यायपालिका, संसद, चुनाव आयोग, सूचना आयोग, और स्वतंत्र मीडिया। लेकिन जब जनता ही इन संस्थाओं के प्रति सम्मान नहीं रखती, तो उनके निर्णयों का महत्व घटने लगता है। कानून का पालन, न्यायिक फैसलों की गरिमा और चुनावी प्रक्रिया की शुचिता की रक्षा नागरिकों की जिम्मेदारी है। अगर हम खुद ही कानून तोड़ेंगे, रिश्वत देंगे, या कोर्ट के निर्णय को जातिगत चश्मे से देखेंगे, तो लोकतंत्र खोखला हो जाएगा।

सामाजिक भागीदारी और राष्ट्र निर्माण

लोकतंत्र का अर्थ केवल सरकार से अपेक्षा करना नहीं है, बल्कि खुद राष्ट्र निर्माण में योगदान देना भी है। स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों, गांवों में काम करने वाले स्वच्छता कर्मचारियों, पर्यावरण के लिए काम कर रहे युवाओं — ये सभी लोकतंत्र के सच्चे स्तंभ हैं। हर नागरिक के छोटे-छोटे प्रयास, जैसे — वोट देना, स्वच्छता में भागीदारी, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, या भाषाई सौहार्द बनाना — लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं।

लोकतंत्र की चुनौतियाँ और हमारी भूमिका

आज लोकतंत्र को कई मोर्चों पर खतरे हैं — ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति, जनता में बढ़ती उदासीनता, सूचना के नाम पर दुष्प्रचार, स्वतंत्र मीडिया और न्यायपालिका पर दबाव।

इन खतरों का सामना केवल संस्थाओं से नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिकों से ही संभव है। जब हर व्यक्ति अपने दायित्व को समझेगा, तब ही लोकतंत्र स्वस्थ रहेगा।

उदाहरणों से सीखें

महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने लोकतंत्र को केवल राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि नैतिक व्यवहार माना। उन्होंने सिखाया कि लोकतंत्र का अर्थ आत्म-नियंत्रण, परस्पर सम्मान और नागरिक सहभागिता है।

आज के दौर में भी अनेक नागरिक चुपचाप बदलाव की मशाल थामे हैं — शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, RTI कार्यकर्ता — जो लोकतंत्र के असली प्रहरी हैं।

समाप्ति: लोकतंत्र को जीवंत रखें

लोकतंत्र एक पौधे की तरह है, जिसे सिर्फ वोट की बारिश नहीं, बल्कि कर्तव्य की खाद और जिम्मेदारी की धूप भी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि भारत एक समावेशी, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील राष्ट्र बने, तो हर नागरिक को आत्मनिरीक्षण करना होगा। "क्या मैं केवल अधिकार चाहता हूँ या उसके साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा हूँ?"

याद रखिए,
"लोकतंत्र मंदिर है, हम उसके पुजारी;
सच्चा नागरिक वही जो निभाए जिम्मेदारी।"

मेयर सुलोचना दास ने अपराजिता शारंगी को आरोप : पार्टी उसके लिए बड़ी है लेकिन सहर नहीं

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : भुवनेश्वर की मेयर सुलोचना दास ने राजधानी के स्थापना दिवस पर सांसद अपराजिता शडगी की अनुपस्थिति पर निराशा व्यक्त की है। सुलोचना ने बताया कि उन्हें स्थापना दिवस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह नहीं आईं। वह दिन भुवनेश्वर का था, जिसका मतलब था ओल्ड टाउन, कपिल प्रसाद, कपिलेश्वर और समंतरपुर जैसे क्षेत्र। विरासत, कला, संस्कृति और परंपरा इस मंदिर-जड़ित शहर की अनूठी पहचान थी। 40,000 की आबादी वाले भुवनेश्वर को राज्य की राजधानी घोषित किया गया और 13 अप्रैल 1948 को इसकी आधारशिला रखी गई। इस क्षेत्र को 1 अक्टूबर 1952 को अधिसूचित क्षेत्र परिषद, 1979 में नगर पालिका और 1994 में भुवनेश्वर महानगर निगम (बीएमसी) का दर्जा दिया गया। इससे पहले, यानी 1 अप्रैल 1983 को भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) के गठन के बाद शहर के विकास की नींव रखी गई थी। इस बीच, राजधानी भुवनेश्वर 77 वर्ष की आयु पार कर चुकी है और अब अपने 78वें वर्ष में है, जो विकास में नए मील के पत्थर स्थापित कर रही है। शहर हर तरफ से बढ़ रहा है। जनसंख्या भी 1.3 मिलियन से अधिक हो गई है। जबकि नए शहरों का निर्माण हो रहा है, भुवनेश्वर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन, परिवहन, आतिथ्य, स्टार्टअप आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। राजधानी की इस लंबी और सफल यात्रा पर एक विशेष प्रस्तुति। स्वच्छ सर्वेक्षण में 34वां स्थान, राज्य में प्रथम। जब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 की घोषणा की गई थी, तो भुवनेश्वर को 80वें स्थान से 34वां स्थान मिला था। इसके अलावा, यह राज्य का पहला शहर बन गया है जिसे वाटर प्लस और कचरा मुक्त शहर के रूप में 3-स्टार रेटिंग मिली है। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वेक्षण में कुल 9500 नंबरों में से भुवनेश्वर को 7314.90 नंबर प्राप्त हुए। इसमें से 51% या 4,830 अंक सेवा स्तर प्रगति के लिए थे, जबकि 26% या 2,500 अंक प्रमाणन के लिए और 23% या 2,170 अंक नागरिक आवाज के लिए थे।

"जयंती का शोर, विचारों से ग़ैरहाज़िरी"

प्रियंका सौरभ

हर चौक-चौराहे पर अब, सजती है एक माला,
बाबा साहब की तस्वीरें, और सस्ती सी दीवाला।
नेता भाषण झाड़ रहा है, मंच सजा है भारी,
पर संविधान की आत्मा है, अब भी बहुत बेचारी।

टोपियाँ नीली, झंडे ऊँचे, लगती क्रांति की टोली,
लेकिन सवाल ये उठता है — कहाँ है वो भूली बोली?
जो कहती थी "हम सब एक हैं", जो गूँज थी अधिकारों की,
आज दबा दिया है वो आवाज़ को नारों की।

मूर्ति की पूजा होती है पर, विचार नहीं अपनाते,
जिसने कड़वा सच लिखा था, उससे क्यों अब कतराते?
जाति रटे न संसद से, न स्कूलों के गलियारों से,
दलित आज भी खड़ा है, न्याय की लंबी कतारों में।

फ्री का राशन दे देकर, सम्मान को बेच रहे,
सत्ता की कुर्सी पर बैठ, संविधान को खींच रहे।
शब्द बड़े हैं भाषण में, कामों में है खोट,
बाबा कहते "समता दो", ये देते वोट की नोट।

बाबा का सपना था — हर जन पावे भाग,
न कोई हो छोटा-बड़ा, न हो कोई परायापन का दाग।
पर आज जयंती के दिन भी, वही दोहराव का गीत,
पिछड़ा, दलित, वंचित वर्ग — बस भाषणों की प्रीत।

नेता वही जो हाथ में माला, मन में पाखंड लिए,
बाबा के नाम पर चलते हैं, पर मन में कपट सिए।
पुस्तकें धूल खा रही हैं, विचारों पर ताले,
फिर भी कहते — "हमने श्रद्धा के फूल डाले।"

जातिगत गणना से डरते, प्रतिनिधित्व से भागते,
उनके नाम पे शपथ तो लेते, पर राह नहीं अपनाते।
जो कहे "हम बाबा के चेले", उनसे मेरा एक सवाल,
क्या संविधान को जीया तुमने, या बस किया इस्तेमाल?

न बंदनवार, न भाषण चाहिए, न ही माला भारी।
बाबा की असली श्रद्धांजलि है — न्याय की जिम्मेदारी।
श्रद्धांजलि जब सच्ची होगी, जब न्याय खड़ा होगा।
बाबा का सपना तब ही, साकार बड़ा होगा।

बाबा तेरा ख़्वाब

फूल चढ़े हर मोड़ पर, भाषण की झंकार।
बाबा तेरे नाम पर, सत्ता करे सवार॥

मंच सजे, माला पड़े, भक्तों का है ढेर।
पुस्तक तेरी धूल में, चुप है हर इक शेर॥

जात न जाए देश से, मिले कहाँ अब न्याय।
सत्ता तेरे नाम पर, लिखती रोज़ अध्याय॥

तेरा जीवन क्रांति था, तेरा धर्म विद्रोह।
आज उसी के नाम पर, सत्ता पाले मोह॥

बोले तूने शब्द जो, वह समता का संदेश।
अनुयायी तेरे यहाँ, भूले वह उपदेश॥

मिला है संविधान तो, मिला नहीं स्वराज।
मगर दलित की आँख में, आँसू है फिर आज॥

हिस्सेदारी, जाति-गण, ये थे तेरे मूल।
मुद्दे आज वह सब बनें, राजनीति के चूल॥

लहराए झंडा सभी, लेकिन बोली मौन।
सत्ता तेरे नाम पे, फिर भी तेरे कौन॥

फ्री राशन से न्याय ना, भीख नहीं सम्मान।
बाबा तेरा ख़्वाब था, देना पूरा स्थान॥

मूर्ति नहीं, विचार हो, सड़क नहीं अधिकार।
श्रद्धांजलि तब सत्य हो, न्याय बने व्यवहार॥

यदि सच में पूजना है, बाबा का आकार।
जीवन में उतारिए, उनके सत्य विचार॥

-डॉ. सत्यवान सौरभ

बाबासाहेब अम्बेडकर के लिए क्या कहूँ...!

मालवा की धरती में इंदौर के समीप हैं महूँ,
मैं बाबासाहेब अम्बेडकर के लिए क्या कहूँ।
इस धरा का ये क्या-क्या न करें हम बखान,
सनातनकाल से पल्लवित व पोशित महान।
सूबेदार रामजी-भीमाबाई का चौदहवाँ फूल,
चौदह को जन्मे भीमराव हमेशा से रहें कूल।

मालवा की धरती में इंदौर के समीप हैं महूँ,
मैं बाबासाहेब अम्बेडकर के लिए क्या कहूँ।
भारत को जातिगत विषमता से मुक्त करने,
वैचारिक, बौद्धिक सम्पदा परिमार्जन करने।
इस महामना ने बहुत अतुलनीय कार्य किया,
ऐसे महामानव ने शताब्दियों में जन्म लिया।

मालवा की धरती में इंदौर के समीप हैं महूँ,
मैं बाबासाहेब अम्बेडकर के लिए क्या कहूँ।
परिवार की आर्थिक परिस्थितियों पर पार,
बाबा साहब उच्च शिक्षा के बल तारणहार।
विदेश में अर्थशास्त्र डॉक्टरेट डिग्री हासिल,
अपनी मेहनत से देशसेवा के लिए काबिल।

मालवा की धरती में इंदौर के समीप हैं महूँ,
मैं बाबासाहेब अम्बेडकर के लिए क्या कहूँ।
दलितों के प्रति छुआछूत का होता व्यवहार,
करते थे विरोध शोषित वर्ग ले रहा आकार।
ज़ब स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना,
बाबासाहेब ने लोकतंत्र का सच किया सपना।

संजय एम तराणेकर

खंडवा के काले परिवार को गौरैया संरक्षण के लिए कलेक्टर ने भेजा प्रशस्ति पत्र

घर की छत को बनाया गौरैयाओं का सुरक्षित आश्रय, पर्यावरण प्रेम की मिसाल बना 'मन गार्डन'

प्रकृति से प्रेम जब समर्पण में बदलता है, तो उसका प्रभाव केवल एक घर तक सीमित नहीं रहता—वह पूरे समाज को प्रेरणा देने लगता है। खंडवा के दादाजी वार्ड निवासी मुकेश काले और उनके परिवार ने अपने घर की छत को 'मन गार्डन' के रूप में विकसित किया है, जो आज गौरैयाओं और अन्य पक्षियों का सुरक्षित और आत्मीय आश्रय बन गया है। इस प्रेरणादायक कार्य के लिए कलेक्टर खंडवा श्री ऋषव गुप्ता द्वारा 8 अप्रैल को काले परिवार के नाम प्रशस्ति पत्र भेजा गया, जिसे पटवारी श्री अशोक सिंह तंवर के माध्यम से उनके निवास स्थान पर प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुकेश काले की पत्नी पूर्णिमा काले, बहू विनीता काले तथा पुत्र अर्थव काले भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने प्रशंसा में लिखा:

"प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में आपके परिवार द्वारा किया गया यह कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। यह समाज को नई दिशा देने वाला प्रेरणादायक प्रयास है। जिला प्रशासन सदैव इस प्रकार के प्रयासों के साथ खड़ा रहेगा।"

'मन गार्डन' बना गौरैयाओं का घर

मुकेश काले ने लगभग दस वर्षों की मेहनत से अपनी छत को हरियाली, लकड़ी के छोटे घरों, दाना-पानी और छायादार स्थानों से सजाया है। अब यह स्थान न सिर्फ गौरैयाओं बल्कि अन्य पक्षियों के लिए भी एक स्वर्ग जैसा बन गया है। उनकी पत्नी पूर्णिमा काले, बहू विनीता काले, और बेटे आदित्य व अर्थव इस सेवा में पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं।

पूर्णिमा काले कहती हैं, ₹अब गौरैया हमारे परिवार का हिस्सा बन गई हैं। उनकी चहचहाहट से दिन शुरू होता है और शाम को लौटती हैं, जैसे ये हमारे अपने घर की सदस्य हों।₹

पर्यावरण प्रेम: जीवनशैली में रचा-बसा संकल्प

जब स्त्रियाँ मायके जाती हैं, तो अक्सर कपड़े, उपहार या पसंदीदा वस्तुएँ साथ ले जाती हैं। लेकिन श्रीमती पूर्णिमा काले का मायके जाना एक अलग ही प्रेरणा देता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनका

समर्पण इतना गहरा है कि वे आज जब अपने मायके इंदौर गईं, तो साथ ले गईं पौधे, कलमें और हरियाली की सौगात। उनका मानना है कि जहाँ भी रहें, वहाँ हरियाली और प्रकृति की सुंदरता ज़रूर हो। यह सोच ही 'मन बगिया' की आत्मा है, और यही भावना उन्हें हर स्थान को प्रकृति से जोड़ने की प्रेरणा देती है।

मित्र भी हुए प्रेरित

मुकेश काले के मित्र हेमंत मोराने बताते हैं कि मुकेश भाई ने यह साबित कर दिया कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उनका यह कार्य न केवल पर्यावरण प्रेम की मिसाल है, बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणा भी है।

प्रकृति संरक्षण की ओर एक प्रेरक संदेश

काले परिवार की यह पहल आज पूरे खंडवा में चर्चा का विषय बन गई है। यह दिखाता है कि यदि संकल्प हो तो प्रकृति से जुड़ाव फिर से स्थापित किया जा सकता है। प्रकृति से जुड़ाव ही सच्चे समृद्ध जीवन की नींव है।

वैश्विक विरासत पर विश्वयुद्ध पूर्व जिस छऊ को मिली थी पहचान आज है तहस नहस

कार्तिक कुमार परिच्छा,स्टेट हेड- झारखंड .

सरायकेला। 16 कलाओं की ऐतिहासिक नगरी ने आजादी के पहले अपनी रियासत की तरफ से राजकुमारों व कलाकारों को साथ लेकर विदेशों में गया था वह देश के करीब 600स्टेटस में से केवल सरायकेला स्टेट था। सरायकेला जो कभी भी मुगल, मराठा या अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा कारण यहां के योद्धा थे। जिसका सांकेतिक प्रमाण यह मार्शल आर्ट का छावनी से आया छऊ। जिसका अनेकों प्रमाण भारत सरकार एवं इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के संग्रहालय में आज भी मौजूद हैं एवं सरायकेला की सांस्कृतिक पृष्टभूमि का विरासत के अनेकों दस्तावेज है ब्रिटिश संग्रहालय मिल जायेंगे। जिसे अपभ्रंश करने की दलालों की कौशिश निरंतर जारी है।

तब विदेशों में किसी को जाना आज के सुनिता विलियम्स की चांद सितारों पर जाने जैसी बात थी पर सरायकेला के लोगों के लिए वह आसान था। कारण यह 16 कला यानी सरायकेला अपनी सामरिककला छऊ को लेकर वहां पहुंचा था। उस समय में ब्रीटिश + इंडिया संयुक्त पासपोर्ट का उपयोग होता था। तब जब भारत दो भागों में बंटा था (Priencly India एवं British India) यही वजह था कि अंग्रेजों को ही अधिकार होता था पासपोर्ट प्रदान करने का चाहे भारत हो या इंग्लैंड। यह वह दौर था दुशरे विश्वयुद्ध के ठीक पहले का सरायकेला का हैसियत वैश्विक कला विरासत पर था। 1936 में युरोप के अनेकों देशों में सरायकेला रायल ट्रप ने धूम मचाई थी परन्तु दुर्भाग्यवश दुशरे विश्वयुद्ध आरंभ का आगाज हो जाने के कारण कलाकारों को शीघ्र लौटना पड़ा था।

पर उसी ओड़िया कला को नीचा दिखा कर समाप्त करने की मनसा प्रबल रही है अब। अब यह किनका कला है षड्यंत्र के कारण असंभव प्रतीत होता है। उदीयमान कलाकारों को दरकिनार करना उन्हें तहस नहस करना विगत बीस तीस वर्ष से जारी है। जो अब प्रबल है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी रहते हुए इस कला को बचाए रखना है या इसे समाप्त करना -जो उच्चस्तरीय जांच का विषय बना है भारत सरकार के लिए। कुछ षड्यंत्रकारी पर्दे के पीछे से सक्रिय हैं। यद्यपि 1947 में सरायकेला का विलय भारतीय अधिराज्य मे हुआ था। आज सरायकेला छऊ में 200 में से लगभग 80 फिसदी नृत्य गायब प्रायः है। सरकारी संरक्षण के जगह शोषण के कारण ऐसा हुआ है। सच तो यह है कि जिस प्रशासन की जिम्मेदारी इसे बचाने हेतु है वहीं अपना कर्तव्य निभाने में अक्षम नजर आता। विगत तीन दशकों से छऊ विषयक जो पत्रकारों को लिखा कर परोसा जाता उसमे सच्चाई कम कुछ और ज्यादा होती।

आइये आपको हम लिये चलते हैं एक ऐसे अद्वितीय फरिखार (Militia) कौम के पास जो उस जमाने में महारानी के दरबार में गये गये थे। जिस नृत्य का उद्गम में फरिखंडा युद्ध कौशल से होता है उसमें कलात्मकता का बोध कुंवर विजय प्रताप सिंह देव ने भरा हैं। आज वे किस पताल में पहुंचा दिये गये किसी सरकार को पता भी है ?

मार्शल यानी युद्धफिल्ड से आये चारू दरोघा एवं दुलो दरोगा परिवार (पद्मश्री स्व मकरध्वज दरोघा पद्मश्री के पिता एवं चाचा) सरायकेला स्टेट के राजकीय सेना में उत्कलीय भी खड्ग धारी खंडायत हुआ करते थे। जो सरायकेला मातृभूमि माटी के लिये युद्ध भी किया करते थे। जब विदेश इंग्लेंड के थिएटर में 1936 में पहली बार छऊ की अखाड़ा बनी तब विदेशी मिडिया ने मुखरित होकर लिखा था -The Hindu dance of India from Seraikella State.

तब सरायकेला की घट-पाट यानी अध्यात्मिक पुजा पाठ तांडव-लास्य

वाद्य, भाव, रस युक्त मुखौटों का बखान पहले से मिडिया ने छप कर सोलह कलाओं की धरती सरायकेला पर चार चांद युरोप में लगा चुका था। जो अतीत में एक संपन्न ओडिया देशी रियासत होने का प्रमाण प्रस्तुत करता था समुचे दुनिया में।

यद्यपि मकरध्वज दरोगा के पिता जी एवं उनके पूर्वजों ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र नारायण सिंहदेव साथ जाकर उन्हें बोलांगीर में सत्तासीन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये है अपने ढाल तलवार के साहरे। आज भी ओडिशा के आर एन सिंहदेव की धरती से उनका इतिहास राजनीति के साथ जूड़ा मिलेगा। जब वे सरायकेला राजकुमार से जाकर राजा बने थे एवं बाद मुख्यमंत्री ओडिशा, उनकी बहन उसी विधानसभा में विधायक हुआ करती थी रत्न प्रभा देवी पूर्व केंद्रीय मंत्री ब्रीगेडियर कामाख्या सिंहदेव की मां। आज झारखंड के राजनीतिक के पद पर कितने जन है, सर्व विदित है। आज उनकी पैतृक धरती पर उनका कला मुरझा रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023